रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, 15 नवम्बर, 1975/कार्तिक 24, 1897

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975/KARTIKA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4778.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 298-चौबेपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवेन्द्र नारायण, ग्राम बैरी, पो० आ० शिवराजपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवेन्द्र नारायण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/298/74 (228)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1975

S.O. 4778.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Devendra Nrain, Village Bairi, Post Office Shivrajpur District Kanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 298-Chaubepur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri Devendra Narain to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/298/74 (228)]

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4779.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-औराई निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सागर, ग्राम व पोस्ट खगरिया, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सागर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/247/74(233)]

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1975

S.O. 4779.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sagar, Village and Post Khagaria, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 247-Aurai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sagar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/247/74 (233)]

आदेश

का० आ० 4780.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 271-हंडिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छोटे लाल, ग्राम व पोस्ट मर्रो, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री छोटे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य के चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/271/74(234)]

ORDER

S.O. 4780.—Whereas the Elecion Commission is satisfied that Shri Chhote Lal, Village & P.O. Marron, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 271-Handia assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chhote Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/271/74 (234)]

आदेश

का० आ० 4781.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 271-हंडिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुराज सिंह, ग्राम व पोस्ट गिर्द कोट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई भी पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा उक्त श्री रघु राज सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/271/74(235)]

ORDER

S.O. 4781.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raghuraj Singh, Village and Post Office Girdkot, District—Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 271-Handia assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raghuraj Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/271/74 (235)]

आदेश

का० आ० 4782.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 271-हंडिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुधिराम, ग्राम कसोधन उर्फ लच्छागिढ़, पो० लच्छागिढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा उक्त श्री सुधिराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०-271/74 (236)]

ORDER

S.O. 4782.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sudhi Ram, Village Kasodhan urf Lachchhagarh, Post Office Lachchhagarh, Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 271-Handia assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sudhi Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/271/74 (236)]

आदेश

का० आ० 4783.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 388-गाजियाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगन्नाथ शर्मा, 18 ब्लाक बी, मोहन नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगन्नाथ शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०-388/74/(237)]

ORDER

S.O. 4783.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagannath Sharma, 18 Block B, Mohannagar Ghaziabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 388-Ghaziabad, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagannath Sharma to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/388/74 (237)]

आदेश

का० आ० 4784.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 388-गाजियाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामफल, मकान नं० 76, कल्लूपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा उक्त श्री राम फल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/388/74 (238)]

ORDER

S.O. 4784.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramphal, House No. 76, Kalloopura, Ghaziabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 388-Ghaziabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramphal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/388/74(238)]

आदेश

का० आ० 4785.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 388-गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री संत लाल, 195-15 प्रेम नगर, गौशाला रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री संत लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं उ० प्र०-वि० स०/388/74(239)]

ORDER

S.O. 4785.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sant Lal, 195-15 Prem Nagar, Goshala Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 388-Ghaziabad, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sant Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/388/74 (239)]

आदेश

का० आ० 4786.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के लिए 388-गाजियाबाद सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बोध राज, 6 जगदीशनगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, श्री बोध राज को जारी की गई सूचना अपरिवत्त वापस प्राप्त हो गई है क्योंकि अभ्यर्थी का ठौर ठिकाना विदित नहीं है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बोध राज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/388/74(240)]

ए० एन० सेन, सचिव

ORDER

S.O. 4786.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bodh Raj, 6 Jagdishnagar, Hapur Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 388-Ghaziabad, Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the notice issued to Shri Bodh Raj has been received back undelivered as the whereabouts of the candidate are not known, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bodh Raj to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/388/74 (240)]
A. N. SEN, Secy

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

आयकर

का० आ० 4787.—अधिसूचना सं० 525 (फा० सं० 203/49/73-आई टी ए-II) तारीख 21 दिसम्बर, 1973 के अनुक्रम में; सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1975 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए अनुमोदित कर दी गई है।

संस्था

महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन आफ साइंस, पुणे।

[सं० 1061 (फा० सं० 203/36/75-आई० टी० ए० 2)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 27th August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4787.—In continuation of notification No. 525 (F. No. 203/49/73-ITA. II) dated 21st December, 1973, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a further period of three years with effect from 1st April, 1975.

INSTITUTION

Maharashtra Association for the cultivation of Science, Poona.

[No. 1061 (F. No. 203/36/75-ITA. II)]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

आयकर

का०आ० 4788.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय समाज-विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है, संस्था अनुसंधान प्रयोजनों के लिये एक पृथक् तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना करेगी जिसमें बहुमत ऐसे व्यक्तियों का होगा, जिनके पास समुचित अनुसंधान सम्बन्धी अनुभव हो और इस अनुमोदन के अधीन केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनों का एक पृथक् लेखा रखेगी और विहित प्राधिकारी को एक वार्षिक रिपोर्ट देगी।

संस्था

समाज कल्याण और विकास अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, मुम्बई।

अधिसूचना 1-4-1975 से 31-3-1978 तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 1078 (फा०सं० 203/62/75-आ०क०अ० 2)]

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4788.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961. The institution will establish a separate Technical Advisory Committee for research purposes with a majority of persons with appropriate research experience and maintain a separate account of all moneys received by the Centre under this approval and submit a report annually to the prescribed authority.

INSTITUTION

The Research & Documentation Centre in Social Welfare and Development, Bombay.

The notification will be effective from 1-4-1975 to 31-8-1978.

[No. 1078 (F. No. 203/62/75-ITA. II)]

नई दिल्ली 10 सितम्बर, 1975

आयकर

का०आ० 4789.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को "विहित प्राधिकारी" भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है।

संस्था

भारतीय राष्ट्रीय आय और धन अनुसंधान संगठन, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी है।

[सं० 1079 (फा०सं० 203/93/75-आई टी ए 2)]

New Delhi, the 10th September, 1975

INCOME TAX

S.O. 4789.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Indian Association for Research in National Income and Wealth, New Delhi.

The notification takes effect from 1st April, 1975.

[No. 1079/F. No. 203/93/75-ITA. II)]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

आयकर

का०आ० 4790.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुमोदित किया गया है:—

(1) संस्थान इस छूट के अधीन प्राप्त सभी निधियों का एक पृथक् लेखा रखे; और

(2) यह प्राप्त निधियां और उनके उपयोग की रीति की बाबत भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

संस्था

कार्वे समाज सेवा संस्थान, पुणे (दा कार्वे इन्स्टीच्यूट ग्रॉफ सोशल सर्विसेज, पुणे)।

यह अधिसूचना 1-7-75 से 31-3-78 तक प्रभावी रहेगी।

[सं० 1080 (फा० सं० 203/41/75-आ०क०अ०II)]

New Delhi, the 15th September 1975

INCOME TAX

S.O. 4790.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax, Act 1961, subject to the following conditions—

(i) The Institution maintains a separate account of all funds received under this exemption and;

(ii) It submits an annual report to the Indian Council of Social Science Research regarding the funds received and the manner in which they were utilised.

INSTITUTION

The Karve Institute of Social Service Poona.

The notification will be effective from 1-7-1975 to 31-3-1978.

[No. 1080 (F. No. 203/41/75-ITA. II)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

आयकर

का० आ० 4791.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि ऐसे क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय-वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों की बाबत जो विशेष सर्किल IV जिला, हावड़ा और विशेष सर्किल V, जिला हावड़ा में समाविष्ट हैं, आयकर आयुक्त के कृत्यों का पालन आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल X, कलकत्ता करेंगे और आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-VI, कलकत्ता नहीं करेंगे।

[सं० 1060/फा०सं० 187/2/74-II (ए/I)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 26th August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4791.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax, West Bengal-X, Calcutta shall and Commissioner of Income-tax, West Bengal-VI, Calcutta shall not perform the function of a Commissioner of Income-tax in respect of such areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases as are comprised in the wards of Special Circle IV, District Howrah and Special Circle V, District Howrah.

This notification shall take effect from 1st of September, 1975.

[No. 1060/F. No. 187/2/74-IT(AI)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

आयकर

का०आ० 4792.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5(6) के अधीन जारी की गई, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 44 II तारीख 1 जुलाई, 1952 में से क्रम संख्या 140 ङ की प्रविष्टि को निकाल देता है और समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (एफ० सं० 55/233/63-II तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित जोड़ता है।

उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 79 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

1	2	3	4	5	6
क्रम सं०	कलकत्ता नगर तथा हावड़ा और चौबीस परगना के सिविल जिलों के क्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी आय पूर्णतः या मुख्यतः मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अधीन यथा परिभाषित ऐसे मोटर यानों का स्वामित्व रखने और/या चलाने से होती है जो भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिये माल या यात्री ले जाने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं।	आयकर अधिकारी जिला III(3) कलकत्ता।	ऐसा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) जो स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया है।	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) जिसमें स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की शक्ति निहित की गई है	आयकर आयुक्त जिसे स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी की बाबत आयकर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया है।

यह अधिसूचना 1-9-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1066/फा० सं० 187/13/75-II(एI)]

टी० पी० झुनझुनवाला, सचिव

New Delhi, the 29th August, 1975

INCOME-TAX

S. O. 4792.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the I.T. Act 1961 (43 of 1961), the C.B.D.T. hereby delets the entry at S. 40E in notification No. 44 IT dated 1st July, 1952 as amended from time to time issued by the Central Board of Revenue u/s 5(6) of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 22) and makes the following addition to the schedule annexed to its notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated 18th May, 1964 as amended from time to time.

After Sl. No. 79 in the said schedule the following shall be added :—

1	2	3	4	5	6
Sl. No.	All persons within the area covered by the City of Calcutta and civil districts of Howrah and 24-Parganas having income wholly or mainly from owner-ship and or playing of motor vehicles as defined under the Motor Vehicles Act 39 (Act IV of 1939) which are used for the carriage of goods or passengers for hire or reward.	Income-tax Office District III(3), Calcutta.	Inspecting Assistant Commissioner of income-tax who has been appointed to perform the function of an Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax in respect of the Income-tax Officer referred to in Col. 3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the Income-tax Officer referred to in Col.s 3.	Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the functions of C.I.T. in respect of the Income-tax Officer referred to in Column 3.

This Notification shall take effect from 1-9-1975.

[No. 1066/F. No. 187/13/75-IT(AI)]
T.P. JHUNJHUNWALA, Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

आयकर

का०आ० 4793.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाले सभी अन्य उपबन्धों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-II) तारीख 18-5-1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधित करता है,

अनुसूची में, क्र० सं० 40 के पश्चात्, क्रम सं० "44-क" जोड़ा जायेगा और इस प्रकार जोड़ी गई क्रम संख्या 44-क के सामने, क्रमश: स्तम्भ 2, 3, 4, 5 और 6 के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी :—

1	2	3	4	5	6
40-क	1 उपनिदेशक, संपरीक्षा और लेखा डाक-तार भोपाल के कार्यालय में सेवारत सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी।	आई टी ओ बी-वार्ड, भोपाल	आई ए सी भोपाल रेंज, भोपाल	ए ए सी भोपाल रेंज, भोपाल	सी आई टी एम पी० I भोपाल
	2 उपनिदेशक संपरीक्षा और लेखा डाक-तार भोपाल के संपरीक्षक नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी सेवक जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर नियुक्त हैं।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

यह अधिसूचना 25-9-1975 से प्रवृत्त होगी

[सं० 1087/फा० सं० 187/7/75-आई टी (ए I)]

New Delhi, the 20th September, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4793.—In exercise of the powers conferred under section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other enabling provisions in this behalf on it, the Central Board of Direct Taxes hereby make the following modifications in the Schedule appended to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated the 18-5-1964, as amended from time to time :

In the Schedule, after S. No. 40, there shall be added S. No. "40-A" and against the S. No. 40-A so added, the following entries shall be added under the 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th columns respectively :

1	2	3	4	5	6
40-A.	1. All Gazetted & Non-Gazetted employees serving in the office of Dy. Director of Audit & Accounts, Posts & Telegraphs, Bhopal.	ITO, B-Ward, Bhopal.	IAC, Bhopal Range, Bhopal.	AAC, Bhopal Range, Bhopal.	CIT, MP-I, Bhopal.
	2. All Govt. Servants under the audit control of Dy. Director of Audit & Accounts, Posts & Telegraphs, Bhopal, posted within the state of Madhya Pradesh.	Do.	Do.	Do.	Do.

This Notifications shall come into force from the 25-9-1975.

[No. 1087/F. No. 187/7/75-IT(AI)]

आयकर

का०आ० 4794.--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का उपान्तरण करते हुए निदेश करता है कि ऐसे कर्मचारियों को जिनका कार्यालय या कार्यस्थान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, नियोजकों द्वारा संदत्त वेतनों से स्त्रोत पर कर की कटौती के कार्य से संबंधित या उससे सम्बद्ध कृत्यों की बाबत अधिकारिता, दिल्ली/नई दिल्ली में नियुक्त सभी अन्य आयकर आयुक्तों को अपवर्जित करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली में निहित होगी।

यह अधिसूचना 25-9-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1089/फा० सं० 187/14/75-आई टी II (ए I)]

एम. शास्त्री, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 4794.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of all previous notifications in this behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the jurisdiction in respect of the functions relating to or connected with work of tax deduction at source from salaries paid to the employees by the employers whose office or place of work is situated in the Union Territory of Delhi shall vest with the Commissioner of Income-tax, Delhi-1, New Delhi to the exclusion of all other Commissioners of Income-tax posted in Delhi/New Delhi.

This notification shall have effect from 25-9-75.

[No. 1089/F. No. 187/14/75-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

आयकर

का० आ० 4795.--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-II (ए I) तारीख 20 जुलाई, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:--

क्रम सं० 23घ, 23ङ, 23च, 23छ, 23ज और 23झ के सामने स्तम्भ 1, 2 और 3 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी :--

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
23घ पश्चिमी बंगाल V	मुख्यालय कलकत्ता	1 जूट सर्किल, कलकत्ता, 2 कम्पनी जिला कलकत्ता, 3 कोआपरेटिव सर्किल कलकत्ता, 4 विदेशी कम्पनी सर्किल, कलकत्ता।
23ङ पश्चिमी बंगाल VI	कलकत्ता	1 हावड़ा, 2 विशेष सर्वेक्षण सर्किल IX कलकत्ता, 3 जिला-iii (3) कलकत्ता, 4 जिला-ii (1), कलकत्ता, 5 विशेष सर्वेक्षण सर्किल IV कलकत्ता।
23च पश्चिमी बंगाल VII	कलकत्ता	1 जिला iii-क, कलकत्ता 2 केन्द्रीय वेतन सर्किल कलकत्ता, 3 जिला V क, कलकत्ता 4 रेल और प्रकीर्ण वेतन सर्किल, कलकत्ता 5 प्रतिदाय सर्किल, कलकत्ता 6 न्यास सर्किल, कलकत्ता, 7 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सर्किल कलकत्ता। 8 बीमा अभिकर्ता सर्किल, कलकत्ता,
23छ पश्चिमी बंगाल VIII	कलकत्ता	1 विशेष अन्वेषण सर्किल I कलकत्ता, 2 जिला ii (2) कलकत्ता 3 परियोजना सर्किल, कलकत्ता,

1	2	3
23ल पश्चिमी बंगाल XIII	कलकत्ता	1 जिला 24 परगना, 2 विशेष सर्वेक्षण सर्किल, VIII कलकत्ता, 3 मुर्शिदाबाद, 4 नादिया, 5 कूच बिहार, 6 दार्जिलिंग, 7 जलपाइगुड़ी, 8 विशेष सर्किल, सिलीगुड़ी, 9 सिलीगुड़ी, 10 पश्चिमी दिनाजपुर, और माल्दा ।
23म पश्चिमी बंगाल XIV	कलकत्ता	1 विशेष अन्वेषण सर्किल ii कलकत्ता, 2 हुगली, 3 मिदनापुर, 4 आसनसोल, 5 बांकुरा, 6 बीरभूमि, 7 बर्दवान, 8 पुरलिया,

यह अधिसूचना 1-10-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1090/फा०सं० 187/2/74-आई० टी० (ए I)]

INCOME-TAX

S.O. 4795.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to the Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated the 20th July, 1974 as amended from time to time.

Existing entries under columns 1, 2 and 3 against Serial Nos. 23D, 23E, 23F, 23G, 23L and 23M shall be substituted by the following entries :—

Income-tax Commissioners	Head Quarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
23D West Bengal-V	Head Quarters, Calcutta.	1. Jute Circle, Calcutta. 2. Comp. Dist. V, Calcutta. 3. Dist. III(2), Calcutta. 4. Co-operative Circle, Calcutta. 5. Foreign Companies Circle, Calcutta.
23E West Bengal-VI	Head Quarters, Calcutta.	1. Howrah. 2. Special Survey Cir-IX, Calcutta. 3. Dist. III(3), Calcutta. 4. Dist. II(1), Calcutta. 5. Special Survey Circle-IV, Calcutta.
23F West Bengal-VII	Head Quarters, Calcutta.	1. Dist. IIIA, Calcutta. 2. Central Salaries, Cir., Calcutta. 3. Dist. VA, Calcutta. 4. Railways & Miscellaneous Salaries Circle, Calcutta. 5. Refund Circle, Calcutta. 6. Trust Circle, Calcutta. 7. Chartered Accountants Cir., Calcutta. 8. Insurance Agents Cir., Calcutta.
23G West Bengal-VIII	Head Quarters, Calcutta.	1. Special Investigation Cir.-I, Calcutta. 2. Dist. II(2), Calcutta. 3. Project Cir., Calcutta.
23L West Bengal XIII	Head Quarters, Calcutta.	1. Dist. 24-Parganas. 2. Special Survey Cir. VIII, Calcutta. 3. Murshidabad. 4. Nadia. 5. Coochbehar. 6. Darjeeling. 7. Jalpaiguri. 8. Special Cir., Siliguri. 9. Siliguri. 10. West Dinajpur & Malda.
23M West Bengal-XIV	Head Quarters, Calcutta.	1. Special Investigation Circle-II, Calcutta. 2. Hooghly, 3. Midnapore, 4. Asansol, 5. Bankura, 6. Birbhum, 7. Burdwan, 8. Purulia.

This Notification shall take effect from 1-10-75.

[No. 1090/F.No.187/2/74-II(AI)]

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

आयकर

का० आ० 4796.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना सं० 886 (फा० सं० 187/2/74-ii (ए० i) तारीख 30-4-75 और सं० 920 (फा० सं० 187/2/64-ii (ए० i) तारीख 29-5-75 में निम्नलिखित परिवर्तन करता है, अर्थात् :—

अधिसूचना सं० 886 तारीख 30-4-75 की क्रम सं० 5क के सामने मद सं० 3 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा ।

क्रम सं०	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
5क	मुम्बई नगर-II	मुम्बई	4 विदेशी कम्पनी सर्किल I

अधिसूचना सं० 920 तारीख 28-5-75 की क्रम सं० 5ख के सामने मद सं० 6 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा ।

5ख	मुम्बई नगर-III	मुम्बई	7 विदेशी कम्पनी सर्किल-II

यह आदेश 1-10-75 से प्रभावी है ।

[सं० 1091/फा० सं० 187/2/74-आई टी (ए I)]

एम० के० पाण्डेय, अवर सचिव ।

New Delhi, the 23rd September, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4796.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of I.T. Act, 1961(43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to its Notification No. 886 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 30-4-75 and No. 920 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dt. 28-5-75.

After Item No. 3 against S. No. 5A of Notification No. 886 dated 30-4-75 the following shall be added.

S. No.	Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
5A	Bombay City-II	Bombay	4. Foreign Companies Circle-I

After Item No. 6 against Sl. No. 5B of Notification No. 920 dated 28-5-75 the following shall be added.

5B	Bombay-City-III	Bombay	7. Foreign Companies Circle-II

This order takes effect from 1-10-75.

[No. 1091/F.No.187/2/74-IT(AI)]

M. K. PANDEY, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1975

का० आ० 4797.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, त्रिचूर जिले में ग्राम पिंकुलम, (डाकखाना तोजुपदम, चेलक्कारा के निकट) में धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड त्रिचूर द्वारा धारित अचल सम्पत्ति (6.02 एकड़ भूमि) के सम्बन्ध में, 4 अक्टूबर, 1976 तक. उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(38)-बी० ओ० III/75]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 3rd October, 1975

S.O. 4797.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act, shall not apply to the Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur, in respect of the immovable property (6.02 acres of land) held by it at Pynkulam village, Thozhupadam, P.O., near Chelakkara, Trichur District, till the 4th October, 1976.

[No. 15 (38)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4798 —भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अक्तूबर, 1975 के दिनांक 17 को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इशु विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	51,33,38,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
संचलन में नोट	6378,60,79,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6429,94,17,000	जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		15,27,89,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		6110,39,75,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयतायें		6429,94,17,000	कुल आस्तियां		6429,94,17,000

दिनांक : 22 अक्तूबर, 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर

17 अक्तूबर, 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयतायें	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	51,33,38,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,12,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,13,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	86,82,72,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	852,32,46,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	744,50,69,000
जमाराशियां :--		निवेश**	414,17,98,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :--	
(i) केन्द्रीय सरकार	107,76,28,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	6,32,54,000	(ii) राज्य सरकारों को†	124,38,34,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :--	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	518,40,23,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को††	186,88,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को$	335,74,73,000
सहकारी बैंक	16,27,21,000	(iii) दूसरों को	12,96,46,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण,	
सहकारी बैंक	1,61,67,000	अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	54,57,000	(क) ऋण और अग्रिम :--	
		(i) राज्य सरकारों को	69·60,45,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,79,23,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	87,00,00,000
(ग) अन्य	1218,89,37,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और	
देय बिल	132,16,04,000	अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	93,69,95,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	741,16,27,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	.
		अन्य आस्तियां	345,97,05,000
रुपये	3762,14,88,000	रुपये	3762,14,88,000

* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†† भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 63,77,00,000 रुपये शामिल हैं।

$ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

के० आर० पुरी, गवर्नर

[सं० फ० 10(1)/75-बी० ओ० I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

दिनांक : 22 अक्तूबर, 1975

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 27th October, 1975

S. O. 4798.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 17th day of October 1975.

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	51,33,38,000		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India . .	182,52,56,000	
Notes in circulation . .	6378,60,79,000		(b) Held outside India .	..	
Total notes issued . . .		6429,94,17,000	Foreign Securities . .	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin . . .		15,27,89,000
			Government of India Rupee Securities		6110,39,75,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities . . .		6429,94,17,000	Total Assets . . .		6429,94,17,000

K. R. PURI Governor

Dated the 22nd day of October, 1975

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 17th October, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
1	2	3	4
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	51,33,38,000
		Rupee Coin	3,12,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,13,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	86,82,72,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills . .	852,32,46,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	744,50,69,000
		Investments**	414,17,98,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	124,38,34,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks† . .	186,88,50,000
(i) Central Government	107,76,28,000	(ii) State Co-operative Banks†† . .	335,74,73,000
(ii) State Governments	6,32,54,000	(iii) Others	12,96,46,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.	
(i) Scheduled Commercial Banks. . .	518,40,23,000		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks .	16,27,21,000		
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,61,67,000	(a) Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	54,57,000	(i) State Governments	69,60,45,000

1	2	3	4
(c) Others	1218,89,37,000	(ii) State Co-operative Banks	12,79,23,000
Bills Payable	132,16,04,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
Other Liabilities	741,16,97,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks.	93,69,95,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank.	333,25,56,000
		(b) Investment in bonda/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	345,97,05,000
Rupees	3762,14,88,000	Rupees	3762,14,88,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

(a) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 63,77,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 22nd day of October 1975.

[No. F. 10(1)/75-BO I]

K. R. PURI, Governor

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4799.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम सूती वस्त्र (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 21क के उपखण्ड (2) में "परन्तु" से प्रारंभ होकर "2 मई 1968 से पूर्व पैक किया होता" अंकों और शब्दों पर समाप्त होने वाले अंश का लोप किया जाएगा।

[फाइल सं० 6/6/75 सूतीवस्त्र I]

दौलत राम, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 4799.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, further to amend the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely :—

1. (1) This Order may be called the Cotton Textiles (Control) Third Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (2) of clause 21A of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, the portion beginning with the words "provided that", and ending with the figures "1968" shall be omitted.

[File No. 6/6/75-Tex. I]

DAULAT RAM, Under Secy.

[मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय]

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4799.—सर्वश्री मिको फार्म केमिकल्ज लि०, मद्रास को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से चेचक नाशक औषधि के निर्माण के लिए फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए 35,500/- रुपये का आयात लाइसेंस संख्या पी०/डी०/2197355, दिनांक 16-3-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बिलकुल उपयोग में नहीं लाई

गई थी और वह किसी भी सीमाशुल्क समाहर्ता के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या: पी०/डी०/2197355, दिनांक 16-3-74 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी को जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या: सी एच/एम-95(1)/ए. एम-74/आर एम-3/1913]

ए० एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 4800.—M/s. Mico Farm Chemicals Limited Madras, were granted Import Licence No. P/D/2197355 dated 16-3-74 for Rs. 35,500 for import of spare parts for the manufacture of Pesticides from General Currency Area. They have requested for issue of duplicate Custom Purpose copy of the licence on the ground that the original Custom Purpose copy has been lost. It has further been stated that the custom purpose copy in question was lost after utilizing Rupees Nil and that the same had not been registered with any of the Collectors of Customs.

2. In support of their contention, the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Custom Purpose copy of Licence No. P/D/2197355 dated 16-3-74 has been lost and directs that duplicate Custom Purpose copy of the said licence should be issued to them. The Original Custom Purpose copy of the licence is cancelled.

[Ref. No. Ch/M-95(1)/A.M. 74/R.M. 3./1913]

A. N. CHATTERJI, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4801.—निदेशक, रेलवे स्टोर्स, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के नाम में जापान से ई एम यू एस के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए 1,79,989 रुपए मात्र का एक लाइसेंस सं० जी/आर/2088143 दिनांक 23-4-71 जारी किया गया था। अब लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय को उसी की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति मद्रास सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने और उस का पूरी तरह उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

अनुरोध के समर्थन में आवेदक ने 5 रुपए के राजकोष चालान के साथ स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० जी/आर/2088143 दिनांक 23-4-71 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि लाइसेंसधारी के नाम में अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस सं० जी/आर/2088143 दिनांक 23-4-71 की मूल सीमाशुल्क प्रति इसके द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या: 50-डी आर एल वाई/70-71/जी एल एस/272]

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1975

S.O. 4801.—An Import Licence No. G/R/2088143 dated 23-4-71 for Rs. 1,79,989 only for the import of Spares for EMUS from Japan was issued in favour of Direct Railway Stores, Railway Board, New Delhi. Now the licensee has requested this office for issue of a Duplicate Customs Copy of the same on the ground that the Original Customs Copy has been lost/misplaced after having been registered with Madras Customs House and fully unutilised.

In support of the request the applicant has filed an affidavit on Stamped Paper alongwith T.R. of Rs. 5.

The undersigned is satisfied that the original Customs Copy of Import Licence No. G/R/2088143 dated 23-4-71 has been lost/misplaced by the applicant and directs that duplicate Customs Copy should be issued in favour of the licensee.

The original Customs Copy of Import Licence No. G/R/2088143 dated 23-4-71 is hereby cancelled.

[No. 50-D/Rly/70-71/GLS/272]

आदेश

का० आ० 4802—निदेशक, मंत्रीमण्डल सचिवालय, कमरा नं 8 बी, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली को थिक्नेस गेज एवं कागज परीक्षक के आयात के लिए एक लाइसेंस सं० जी/ए/1404749 दिनांक 14-10-74 स्वीकृत किया गया था। निदेशक, मंत्रीमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां अस्थानस्थ हो गई हैं और उसी की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देती है कि लाइसेंस की उक्त सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी की जाएं।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द करदी गई है। उसी की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: सेन्ट/181/74-75/पी एल एस/बी/691]

ORDER

S.O. 4802.—The Director, Cabinet Sectt. Room No. 8B, South Block New Delhi was granted licence No. G/A/1404749 dated 14-10-74 for the import of thickness gauge and paper tester. The Director, Cabinet Sectt. has reported that Customs copy and exchange control copy of the licence have been misplaced and has requested to issue duplicate copies of the same.

In support of their contention the applicant has filed a certificate. The undersigned is satisfied that the Custom copy and exchange control copy of the licence have been lost and directs that the duplicate copies of the said customs copy and exchange control copy of the licence be issued.

The original customs copy and exchange control copy of the licence has been cancelled. A duplicate copy of the same is being issued, separately.

[No. Cent/181/74-75/PLS/B/691]

आदेश

का० आ० 4803.—सर्वश्री हाल कानपुर डिवीजन, कानपुर को एक लाइसेंस सं० आई/ए/1396949 दिनांक 4-1-74 स्वीकृत किया गया था। सर्वश्री हाल कानपुर डिवीजन, कानपुर ने यह प्रतिवेदित किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है और उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर वचन दिया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं और निदेश देती है कि लाइसेंस की उक्त सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां जारी की जाएं।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां रद्द कर दी गई हैं। उसी की अनुलिपि सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या : हाल/85/73-74/पी एल एस/ए/पी एल एस/बी/690]

ORDER

S.O. 4803.—M/s. Hal Kanpur Division Kanpur was granted licence No. I/A/1396949 dated 4-1-74. M/s. Hal Kanpur Division Kanpur has reported that the Customs copy and the E.C. Copy of the above mentioned licence has been misplaced and he has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has given undertaking on the stamped paper. The undersigned is satisfied that the Customs and E.C. Copies of the said licence have been lost and directs that the duplicate copy of the said Customs copy and E.C. Copy of the licence be issued.

The Original Customs copy and the E.C. Copy of the licence have been cancelled. Duplicate Customs and E.C. Copies of the same are being issued.

[No. HAL/85/73-74/PLS/A/PLS/B/690]

आदेश

नई दिल्ली, 21, अक्तूबर 1975

का० आ० 4804.—अपर मुख्य अभियन्ता (उत्तर) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना को लाइसेंस सं० जी/ए/1048332 दिनांक 21-1-72 प्रदान किया गया था। विद्युत अधीक्षक बिहार राज्य बिजली बोर्ड पटना ने सूचना दी है कि उपर्युक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियां खो गई हैं और उसने, उस लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर वचन दिया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई हैं और निदेश देता हूं कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी की जायें।

लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती हैं और उन की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[संख्या : 3/एस जी/251/71-72/पी एल एस/बी/692]

ORDER

New Delhi, the 21st October, 1975

S.O. 4804.—The Additional Chief Engineer (North) Bihar State Electricity Board Patna was granted Licence No. G/A/1048332 dated 21-1-72. The Electrical Suptdg. Bihar State Electricity Board Patna has reported that the above mentioned licence in duplicate has been misplaced and he has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has given undertaking on the stamped paper. The undersigned is satisfied that the Custom copy and Exchange Control copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copies of the said licence be issued.

The Customs copy and the Exchange control copy of the licence has been cancelled and duplicate copies of the same are being issued separately.

[No. 3/SG/251/71-72/PLS/B/692]

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4805.—सर्वश्री आइडियल इन्डस्ट्रीज, 111 ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से नमूनों एवं परीक्षण उपकरण के आयात के लिए 7400 रुपए का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1400549/सी/एक्स एक्स/52/एच/39-40-स्पेशल सेल दिनांक 20-8-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उन के बैंक, नई दिल्ली द्वारा खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। उन्होंने आगे यह बताया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमाशुल्क कार्यालय पालम, नई दिल्ली में पंजीकृत करवाई गई है। कुल धनराशि जिस के लिए लाइसेंस जारी किया गया था वह 7400 रुपए है और कुल धनराशि जिस के लिए मूल प्रति का उपयोग कर लिया गया था वह 1428 रुपए मात्र है और शेष 5,972 रुपए का उपयोग नहीं किया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि लाइसेंस सं० पी/ए/1400549 दिनांक 20-8-74 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देती है कि उन्हें उक्त लाइसेंस अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या पी० स्पेशल/30/टी०डी०ए०/73-74/582]

एस० के० उस्मानी, उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1975

S.O. 4805.—M/s. Ideal Industries, 111 Okhla Industrial Estate, New Delhi were granted Import Licence No. P/A/1400549/C/XX/52/H/39-40-SP, CELL dated 20-8-1974 for the import of Samples and Test Equipment valued at Rs. 7,400 only from G.C.A. They have requested this office for issue of Duplicate Exchange Control Copy of the Licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost/misplaced by their Bank concerned at New Delhi. They have further stated that the original Exchange Control Copy of the licence having been registered with Palam New Delhi Customs House. The total amount for which the licence was issued is Rs. 7,400 only and the total

amount for which the original copy was utilised is Rs. 1,428 only and the balance of Rs. 5,972 only was unutilised.

2. In support of their contention, the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the licence No. P/A/1400549 dated 20-8-1974 has been lost/misplaced and directs that duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence should be issued to them. The original Exchange Control Purposes copy is cancelled.

[F. No. P/SPCL/30/TDA/73.74/582]

S. K. USMANI, Dy. Chief Controller

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4806.—मेगनोलिया रेस्तरां 12-के, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता 16 को 1,500 रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1400362 दिनांक 13-6-74 खाद्य सामग्री (लाइसेंस से संलग्न सूची के अनुसार) आयात करने लिए प्रदान किया गया था। संस्था ने आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1400362 दिनांक 13-6-74 की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे खो गई है।

पार्टी ने आवश्यक शपथ पत्र/घोषणा पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उक्त लाइसेंस किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं करवाया है और वह बिल्कुल उपयोग में नहीं लाया गया है। घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया गया है कि सीमाशुल्क प्रति यदि बाद में मिल गई या पता लग गया तो वह लाइसेंस प्राधिकारी को रिकार्ड के लिए वापिस कर दी जायेगी। मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति संलग्न सूची के समेत खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। आयात लाइसेंस पी/ए/1400362, दिनांक 13-6-74 की मूल सीमाशुल्क प्रति इसके द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या एन० डी० 12/347/74-75/एम एलI/924]

नवरेखा शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 23rd October, 1975

S.O. 4806.—Mangolia Restaurant 12-K Park Street, Calcutta-16 were granted Licence No. P/A/1400362 dated 13-6-74 for c. i. f. value of Rs. 1,500 for the importation of Provisions (as per list attached). The party has approached this office for grant of a duplicate Customs Copy of Import Licence No. P/A/1400362 dated 13-6-74 on the ground that the original one has been lost by them.

The necessary affidavit/declaration has been furnished by the party according to which the aforesaid licence has not been registered with any Customs House and not utilised at all. It has also been incorporated in the declaration that if the said Customs Copy of Import Licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority for record. I am satisfied that the original Customs purpose Copy of Import Licence alongwith the list of goods has been lost/misplaced and direct that duplicate should be issued to the applicant. The original Customs Copy of Import Licence No. P/A/1400362 dated 13-6-1974 is hereby cancelled.

[File No. 12/347/74-75/ML.I/924]

NAVREKHA SHARMA, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1975

का० आ० 4807.—सर्वश्री केबल कारपोरेशन आफ हरियाणा, गांव रसोई, डाकघर कुन्डली जिला सोनीपत के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को अप्रैल-मार्च 74 अवधि के लिए 37,500 रुपये मूल्य का एक लाइसेंस सं० जी/टी/2404927 दिनांक 18-9-74 अंतिम उपयोग रबड़ शीट के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से संश्लिष्ट रबड़ के आयात के लिए जारी किया गया था।

2. पार्टी ने सूचना दी है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल भी उपयोग किए बिना और किसी भी पत्तन पर पंजीकृत कराए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उसको रद्द करने का आवेदन किया है। इसकी अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए भी पार्टी ने आवेदन किया है। उपर्युक्त कथन के समर्थन में पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैन्ड बुक, 1974-75 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 के खंड 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस की पूर्वोक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. अब आवेदक को सामान्य मुद्रा क्षेत्र पर 37,500 रुपए के लिए जारी किए गए पूर्वोक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैन्ड बुक, 1974-75 के पैरा 320 (4) की शर्त के अनुसार जारी की जा रही है।

[संख्या एन पी/सी-6(एन)/ए एम 74/ए यू एच एच/सी एल ए/379]

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS)

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1975

S.O. 4807.—Licence No. G/T/2404927 dated 18-9-74 was issued to S. T. C. New Delhi with Letter of Authority in favour of M/s. Cable Corporation of Haryana, Village Rasoi, P. O. Kundli Distt. Sonepat for Rs. 37,500 on G. C. A. for import of Synthetic Rubber for AM. 74 period for the end use Rubber sheet.

2. The party have intimated that the Exchange copy of the above said licence has been lost/misplaced without having been utilized at all and withuot having been registered at any port and have requested for cancellation thereof. Party have also requested to issue duplicate Exch. Control copy of the same. The party have filed an affidavit in support of above statement as required vide para 320 of STC Hand Book of Rules and Procedure, 1974-75.

3. In exercise of the power conferred on me under section 9(cc) of Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955, I order the cancellation of the aforesaid Exch. Control Purposes of copy of the licence.

4. The applicant is now being issued duplicate Exch. Control copy of he aforesaid licence for Rs. 37500 on GCA in accordance with the provision of para 320(4) of the ITC Hand Book of Rules & Procedure 1974-75.

[No. NP/C-6(N)/AM.74/AU.HH/CLA/379]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller
of Imports and Exports
for Joint Chief Controller of Imports & Exports

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का० आ० 4808.—सर्वश्री रमन इन्डस्ट्रीज 87-बी इन्डस्ट्रियल इस्टेट लुधियाना को 6,279 रुपए मूल्य मात्र तक के सभी वर्गों के उच्च गति इस्पात स्क्वेयर 10 एम एम से कम और स्क्वेयर 10.5 एम एम, 17.5 एम एम और 20.5 एम एम का आयात करने के लिए दो लाइसेंस सं० पी/एस/1802905 दिनांक 21-11-73 मूल्य 12,559 रुपए और पी/एस/1802906 दिनांक 2-11-73 मूल्य 12,559-रुपए प्रदान किए गए। उन्होंने सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनकी मूल प्रतियां बिना प्रयोग किए ही खो गई या अस्थानस्थ हो गई।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 के परिशिष्ट के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 320(2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित स्टाम्प कागज पर शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां अस्थानस्थ हो गई हैं।

मैं आज तक के यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-1-1955 की धारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं० पी/एस/1802905 दिनांक 2-11-73 और पी/एस/1802906 दिनांक 2-11-73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं।

आवेदक के मामले पर आयात व्यापार नियंत्रण, नियम और क्रियाविधि पुस्तक 1975-76 पैरा 320 के अनुसार उक्त लाइसेन्स की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि जारी करने के लिए अब विचार किया जायेगा।

[सं० पी०/आर० 3/ए० एम०-74/ए० यू० पी० बी०/सी०एल०ए०/1467]

पी० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4808.—M/s. Raman Industries, 87-B, Industrial Estate, Ludhiana were granted import licences Nos. P/S/1802905 dated 2-11-73 for Rs. 12,559 & P/S/1802906 dated 2-11-73 for Rs. 12,559 both for import of High Speed Steel of all grades square below 10 MM & Square 10.5 MM, 13.5 MM, 17.5 MM & 20.5 MM up to Rs. 6,279 only. They have applied for duplicate Customs purposes copies of the licences on the ground that the original have been lost/misplaced without having been utilized at all.

2. The applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under para 320(2) read with appendix 8 of I.T.C. Hand Book of Rules and procedure 1975-76. I am satisfied that the original Customs purpose copies have been misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under clause 9(cc) Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-55 as amended up to date, I order the cancellation of Customs purpose copies of the licence No. P/S/1802905 dated 2-11-73 & P/S/1802906 dated 2-11-73.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate Customs purpose copies of the above licences in accordance with para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76.

[File No. P/R-3/AM-74/AU.PB/CLA/1467]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller
for Joint Chief Controller

(उपमुख्य नियन्त्रक आयात निर्यात का कार्यालय)

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

हैदराबाद, 14 जुलाई, 1975

का० आ० 4809.—सर्वश्री ज्योति पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद को 49,000 रुपये (उन्चास हजार रुपये मात्र) मूल्य का एक लाइसेंस सं० पी/एस/1742885/सी/एक्स एक्स/50/डब्ल्यू/37/38 दिनांक 24-1-74 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 322 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस सं० पी/एस/1742855/सी/एक्स एक्स/50 डब्ल्यू/37-38 दिनांक 24-1-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. अब आवेदक के मामले पर आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 के पैरा 320 के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए विचार किया जाएगा।

[संख्या जे-18/एस एस आई/पी-52/ए एम-74/हैद०]

आर० कुमारवेलू, उप-मुख्य नियंत्रक

(OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF COTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS)

CANCELLATION ORDER

Hyderabad, the 14th July, 1975

S.O. 4809.—M/s. Jyothi Paints & Chemicals, University Road Hyderabad were granted licence No. P/S/1742885/C/XX/50/W/37-38 dated 24-1-74 for Rs. 49,000 (Rupees forty nine thousand only). They have now applied for issue of duplicate copy of the Exchange Control copy of the above licence on the grounds that the original copy has been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under para 322 read with Appendix-8 of the Import made Control Hand Book of Rules and procedure, 1975-76. I am satisfied that the original Exchange Control purposes copy has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Clause 9(cc) of Import (Control) Order 1955, dater 7-12-1955 as amended up to date. I order the cancellation of the Exchange control of licence No. P/S/1742855/C/XX/50/W/37-38 dated 24-1-1974.

4. The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate Exchange Control purposes copy of the above licence in accordance with para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & procedure, 1975-76.

[File No. J-18/SSI/P-52/AM-74/Hyd]

R. KUMARAVELU, Dy. Chief Controller

आदेश

अहमदाबाद, 18 सितम्बर, 1975

का० आ० 4810.—सर्वश्री रेनबो फोटोएनग्रेवर्स एन्ड रेनबो टेक्सटाइल एनग्रेवर्स, 4229 शाहपुर मिल कम्पाउन्ड, अहमदाबाद को अप्रैल-मार्च 1975 लाल पुस्तक के अनुसार एक्स-रे फिल्म और निर्णय मदों को छोड़कर

फोटोग्राफिक निगेटिव और मुद्रण कागज के आयात के लिए 10410/ रुपये (दस हजार चार सौ दस रुपये मात्र) मूल्य का एक लाइसेंस सं० पी/एस/1399028 दिनांक 10-6-74 प्रदान किया गया है ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क-निकासी प्रति) की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० 1399028 दिनांक 10-6-74 की मुद्रा विनिमय और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता हूं कि इन की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को फर्म को जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क निकासी प्रति अब से रद्द कर दी गई समझी जाती है ।

[मि० सं० 1340/ईयू/28534/एनपी/एएम 74/एयू/एसएसआई/4563]

डी० डी० सूजा, उप-मुख्य नियंत्रक

S.O. 4810.—M/s. Rainbow Photoengravers & Raiinbow Textile Engravers 4229. Shahpur Mill compound, Ahmedabad, has been granted Licence No.P/S 1399028 dated 10-6-74 for Rs. 10410 (Rs. Ten Thousand Four Hundred and Ten only) for Imports of Photographic Negative and Printing paper excluding X-Ray. Film and banned items a per AM75 Red Book.

They have applied for duplicate copies of the said Licenes (Exchange Control Purpose copy and Custom Purpose copy) On he ground that the original Exchange Control purpose copy and Custom purpose copy have been lost/Misplaced without having been registered with any Custom authority.

In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that Exchange Control Purpose copy and Custom purpose copy of Licence No. 1399028 dated 10-6-74 has been lost and direct that the duplicate of the said Exchange Control purpose copy and Custom purpose copy of the Licence should be issued to applicant firm.

The original Exchange Control purpose copy and Custom purpose copy of the Licence are treated as cancelled, herewith.

[No. 1340/EU/28534/N.P./AM.74/AU/SSI/4563]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4811.--कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री श्रीनिवास कार्यलिर के निधन से हुई रिक्ति पर श्री थेकडी प्रभाकरन्, अध्यक्ष, अलेप्पी सेन्ट्रल कयर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, अलेप्पी (केरल) को 23 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कयर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 406 (ई०) जो 24 जुलाई 1973 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, (क) "नारियल उगाने वाले और जटा कयर यार्न के उत्पादकों" के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित लिखा जायेगा, अर्थात् :—

"1. श्री थेकडी प्रभाकरन्, अध्यक्ष, अलेप्पी सेन्ट्रल कयर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, अलेप्पी (केरल) ।"

[फा० सं० 16/1/75-सी० एण्ड एस]

एस० एन० घोष, उप-निदेशक (आई० सी०)

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 10th October, 1975

S.O. 4811.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Shri Thachady Prabhakaran, President, Alleppey Central Coir Marketing Cooperative Society, Alleppey (Kerala) as a member of the Coir Board for the period ending with the 23rd day of July, 1976 against the vacancy caused by the demise of Shri Srinivasa karayalar and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 406(E) published in the Government of India Extraordinary dated 24th July, 1973, namely :—

In the said notification, for the entry against serial number 1 under "(a) Growers of Coconuts and producers of husks and Coir Yarn", the following shall be substituted, namely :—

"1. Shri Thachady Prabhakaran, President, Alleppey Central Coir Marketing Cooperative Society, Alleppey (Kerala)".

[F. No. 16/1/75-C&S]

S. N. GHOSH, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4812.--उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवम विकास परिषद (कार्यविधि) नियम 1962 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का० आ० पी०/डी० सी०/आई० डी०/73 दिनांक 9 जुलाई, 1973 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया के अधीन नियुक्त किये गये सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, 15 अक्तूबर, 1975 से दो वर्षों की अवधि के लिये कागज, लुग्दी तथा सहबद्ध उद्योगों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है :--

कागज, लुग्दी और सहायक उद्योगों की विकास परिषद:

क्र सं०	नाम	प्रतिनिधित्व
1.	श्री एम० एल० जुसी, सी० एम० डी०, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन।	अध्यक्ष
2.	श्री एन० वी० दास गुप्ता, सी० एम० डी०, नेपा मिल्स।	सदस्य
3.	अध्यक्ष, कागज उद्योग की संयुक्त समिति।	सदस्य
4.	डा० एम० के० रैना, उपाध्यक्ष, बेलारपुर पेपर एंड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड।	सदस्य

क्र० सं०	नाम	प्रतिनिधित्व
5.	श्री जे० सी० अग्रवाल, बंगाल पेपर मिल्स।	सदस्य
6.	प्रधान, इंडियन पल्प एंड पेपर टैक्नीकल एसोसियेशन, इन्स्टीट्यूट आफ पेपर टैक्नालाजी, सहारनपुर।	सदस्य
7.	श्री एस० विश्वनाथन, प्रबन्ध निदेशक, शेषशायी पेपर एंड बोर्डस लि०।	सदस्य
8.	श्री एन० एस० सदावर्ते, महाप्रबन्धक, सेंट्रल पल्प मिल्स।	सदस्य
9.	श्री बी० डी० सोमानी, निदेशक, वेस्टकोस्ट पेपर मिल्स।	सदस्य
10.	श्री एच० एस० सिंहानियां, प्रबन्ध निदेशक, स्ट्रा प्रोडक्टस लि०।	सदस्य
11.	श्री के० एल० राजगढ़िया, पार्टनर, राजेन्द्र पेपर मिल्स।	सदस्य
12.	डा० आर० एल० भार्गव, अध्यक्ष, भार्गव डिजाइन एंड कन्सल्टिंग इंजीनियर्स।	सदस्य
13.	श्री एन० नरसिंहन, प्रबन्ध निदेशक, सेल्युलोसिक कन्सल्टैन्टस इंडिया प्रा० लि०।	सदस्य
14.	सेल्यूलोस शाखा के प्रधान, वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून (उत्तर प्रदेश)।	सदस्य
15.	प्रधान, इंस्टीट्यूट आफ पेपर टैक्नालाजी, सहारनपुर।	सदस्य
16.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
17.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का एक प्रतिनिधि, रफी मार्ग, नई दिल्ली।	सदस्य
18.	प्रधान, आल इंडिया स्माल पेपर मिल्स एसोसियेशन, बम्बई।	सदस्य
19.	प्रधान, आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स, नई दिल्ली।	सदस्य
20.	श्री आर० सी० सरीन, निदेशक, इंडियन टोबैको कम्पनी लि०।	सदस्य
21.	प्रधान, फेडरेशन आफ पेपर ट्रेडर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, बम्बई।	सदस्य
22.	प्रधान, इंडियन नेशनल पेपर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन, जिला हुगली (पं० बंगाल)	सदस्य
23.	राज्य सभा का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
24. और 25.	लोक सभा के दो प्रतिनिधि।	सदस्य
26.	अध्यक्ष, पेपर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता।	सदस्य
27.	श्री आर० जे० साहनी, प्रबन्ध निदेशक, जैसप एंड कम्पनी लि० कलकत्ता।	सदस्य
28.	श्री एम० सत्यपाल, सलाहकार, (इंडस्ट्री एण्ड मिनरल्स डिवीजन) योजना आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
29.	प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे आफ फारेस्ट रिसोर्सेज, देहरादून, का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
30.	श्री ए० एन० राव, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य सचिव

तकनीकी विकास के महानिदेशालय, नई दिल्ली में विकास अधिकारी श्री ए० एन० राव को एतद्द्वारा उक्त विकास परिषद के कार्य संचालन के लिये सचिव नियुक्त किया जाता है।

[पी० डी० सी० आई० डी० 75-सं० 3(38)/75-कागज]

कौशल कुमार माथुर, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 29th October, 1975

S. O. 4812.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the 15th October, 1975 the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled industries engaged in the manufacture or production of Paper, Pulp and Allied Industries, in place of members appointed under the Government of India in the late Ministry of Industrial Development Order No. SOP/DC/ID/73 dated the 9th July, 1973 as amended from time to time, whose tenure of office has expired.

Development Council For Paper, Pulp And Allied Industries

Sl. No.	Name	Represent
1.	Shri M.L. Zutshi, Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Paper Corporation.	Chairman
2.	Shri N.B. Das Gupta, Chairman-cum-Managing Director, Nepa-mills.	Member
3.	Chairman, Joint Committee of Paper Industry.	Do.
4.	Dr. M.K. Raina, Vice President, Ballarpur Paper & Straw Board Mills Limited.	Do.
5.	Shri J.C. Aggarwal, Bengal Paper Mills.	Do.
6.	President, Indian Pulp & Paper Technical Association, Institute of Papers Technology, Saharanpur.	Do.
7.	Shri S. Vishwanathan, Managing Director, Seshasayee Paper & Board Limited.	Do.
8.	Shri N.S. Sadavarte, General Manager, Central Pulp Mills.	Do.
9.	Shri B.D. Somani, Director, West Coast Paper Mills.	Do.
10.	Shri H.S. Singhania, Managing Director Straw Products Ltd.	Do.
11.	Shri K.L. Rajgharia, Partner, Rajendra Paper Mills.	Do.
12.	Dr. R.L. Bhargava, Chairman, Bhargava Design & Consulting Engineers.	Do.
13.	Shri N. Narasimhan, Managing Director, Cellulosic Consultants (India) Private Limited.	Do.
14.	Head of the Cellulose Branch, Forest Research Institute, Dehra Dun, U.P.	Do.
15.	Principal, Institute of paper Technology, Saharanpur.	Do.
16.	One representative of the Department of Science and Technology, Technology Bhavan, New Delhi.	Do.

Sl. No.	Name	Represent
17.	One representative of the Council of Scientific and Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi.	Member
18.	President, All India Federation of Master Printers, New Delhi.	Do.
19.	President, All India Small Paper Mills Association, Bombay.	Do.
20.	Shri R.C. Sarin, Director, Indian Tobacco Co. Ltd.	Do.
21.	President, Federation of Paper Traders Association of India, Bombay.	Do.
22.	President, Indian National Paper Mill workers Federation, District Hoogly (W.B.).	Do.
23.	One representative from Rajya Sabha	Do.
24. & 25.	Two represent atives from Lok Sabha	Do.
26.	Chairman, Paper Machinery Mfg. Association, Calcutta.	Do.
27.	Shri R.J. Shahaney, Managing Director, Jessops & Co. Ltd., Calcutta.	Do.
28.	Shri M. Satyapal, Additional Adviser, (Industry and Minerals Division). Planning Commission, New Delhi.	Do.
29.	One representative of Pre-Investment Survey of Forest Resources, Dehra Dun.	Do.
30.	Shri A.N. Rao, Development Officer, D.G.T.D., Udyog Bhavan, New Delhi.	Member/ Secretary

Shri A.N. Rao, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi, is hereby appointed to carry on the functions of Secretary of the said Development council.

[P./D.C./I.D/75-No. 3(38)/75-Paper
K.K. MATHUR, Directo

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर 1975

का० आ० 4813--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (कार्य-विधिक) नियम, 1952 के नियम 3 और 4 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 23(अ), तारीख 9 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश में, क्रम सं० 14 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात् :—

"14. प्रधान, सदस्य

फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया" ;

[सं० 1(2)/अनुज्ञप्ति नीति/74]
भारत भूषण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1975

S.O. 4813.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 4 of the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 23(E), dated the 9th January 1975, namely :—

In the said order, for serial No. 14 the following serial No. shall be substituted namely :—

"14. President, Member
Federation of Association of
Small Industries of India".

[No. 1(2)/Lic. Pol./74]
BHARAT BHUSHAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

का. आ. 4814.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) चीनी निदेशक तमिलनाडु सरकार मद्रास (2) चीनी निदेशक, महाराष्ट्र राज्य पूणे, तथा (3) चीनी निदेशक, आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद, को, 12 जून, 1976 तक की अवधि के के लिए जिसमें वह दिन भी सम्मिलित करके, चीनी उद्योग विकास परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या, एस.सी.ओ. 1687/आई. डी. आर. ए/6/4/74, तारीख 13 जून, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम संख्याओं 9, 10 और 11 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"9. चीनी निदेशक, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ,

10. चीनी निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे,

11. चीनी निदेशक, आन्ध्र प्रदेश, उद्योग और वाणिज्य (चीनी) विभाग, हैदराबाद ।"

[आई. डी. आर. ए. 6/8/75 सं. 8/4/74-सी. डी. एन.]
प्रेम नारायण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1975

S.O. 4814.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints (i) Director of Sugar, Government of Tamil Nadu, Madras, (ii) Director of Sugar, Maharashtra State, Poona, and (iii) Director of Sugar, Andhra Pradesh, Hyderabad, as members of the Development Council for Sugar Industry for the period upto and inclusive of the 12th June, 1976, and makes the following amendments in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 1687/IDRA/6/4/74, dated the 13th June, 1974, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, for serial number 9, 10 and 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely :—

"9. Director of Sugar,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

10. Director of Sugar,
 Maharashtra State,
 Poona.

11. Director of Sugar,
 Andhra Pradesh, Industries and
 Commerce (Sugar) Department,
 Hyderabad.".

[No. IDRA/6/8/75—No. 8/4/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4815.--वन्य प्राणि संरक्षण के सहायक निदेशक श्री के० विश्वानाथन को एतद्द्वारा वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972, की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है।

[सं० जे० 13011/7/75-एफ० डी० (डब्ल्यू० एल० एफ०)]

एस० ए० शाह, निदेशक

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 10th October, 1975

S.O. 4815.—Shri K. Viswanathan, Assistant Director, Wild Life Preservation is hereby authorised to exercise powers under section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

[No. J. 13011/7/75-FD (WLF)]

S. A. SHAH, Director

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4816.--राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त विभाग के पत्र सं० 104-सी० एस० आर०, तारीख 4 फरवरी, 1922 के साथ जारी किये गये अनुपूरक नियमों के खंड XXVI के अन्तर्गत नियमों में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1.(1) इन नियमों का नाम, वन अनुसन्धान संस्थान तथा महाविद्यालय देहरादून, वन अनुसन्धान प्रयोगशाला बंगलौर, दक्षिणी वन रेंजर महाविद्यालय तथा वन अनुसन्धान केन्द्र कोयम्बटूर में सरकारी निवास स्थानों का आबंटन (राजपत्रित) तथा अराजपत्रित सरकारी सेवकों के लिये वास सुविधा पूल (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अ० नि० 317-आबंटन 8 के उपनियम 5 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु जब कोई आबंटन एक मास की अवधि के समाप्त होने की तारीख से पूर्व ही रद्द कर दिया जाता है, तब ऐसे रद्दकरण के कारण लेख बद्ध किये जायेंगे।"

3. अ० नि० 317-आ० 18 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:--

"परन्तु उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"

[सं० जी० 11025/28/74-एफ० आर० वाई०-एफ०]

रूप राम, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1975

S.O. 4816.—In pursuance of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the rules under Division XXVI-AL of the Supplementary Rules issued with the Government of India, late Finance Department letter No. 104-CSR, dated the 4th February, 1922, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences in the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, Forest Research Laboratory, Bangalore, Southern Forest Rangers College and Forest Research Centre, Coimbatore (Pool accommodation for Gazetted and Non-Gazetted Government servants) (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. To sub-rule (5) of S.R. 317-AL-8, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the allotment is cancelled with effect from a date prior to the expiry of the period of one month, the reasons for such cancellation shall be recorded in writing".

3. After sub-rule (2) of S.R. 317-AL-18, the followingp roviso shall be added, namely :—

"Provided that before taking action under sub-rule (1) or sub-rule (2), the officer concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard".

[No. G. 11025/28/74-FRY-F.]

RUP RAM, Under Secy.

(अन्तरिक्ष विभाग)

बंगलौर, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 4817.—भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम 45 के उपबन्ध के अनुसार, अन्तरिक्ष विभाग, एतद्द्वारा अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद के इंजीनियरी सेवा प्रभाग को, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा के सर्विसिज फैसीलिटी प्रभाग को, श्री हरिकोट स्थित श्री हरिकोट रेंज केन्द्र के सर्विसीज फैसीलिटी प्रभाग को और अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग को, सारे भारत में स्थित इसकी यूनिटों के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम 45(1) के प्रभाव से छूट प्रदान करता है, जहां तक इसका राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस शुदा विद्युत् ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के कार्यान्वियन का सम्बन्ध है।

जिन कार्यों के बारे में छूट दी गई है, वे हैं, सभी प्रकार के विद्युत् संस्थापनों में परिवर्धन परिवर्तन, तथा नये कार्य, भले ही उनकी कितनी भी वोल्टेज हो।

विद्युत् संस्थापना सम्बन्धी कार्य किसी योग्य और सक्षम विद्युत् इंजीनियर के सीधे पर्यवेक्षण में किया जायेगा और यह किसी योग्य और सक्षम कारीगर द्वारा किया जायेगा।

विभागीय तौर पर किये गये किसी भी संस्थापन कार्य के पूरा किये जाने के तत्काल बाद, जिस विद्युत् इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कार्य किया जा रहा हो, वह विद्युत संस्थापनों के चालू होने से पहले यह प्रमाणित करेगा कि वह कार्य पूर्णतया भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के अनुरूप सन्तोषजनक ढंग से किया गया है।

[सं० 5/11(5)/75-II]

एन० एस० आचार्य, अवर सचिव,

(DEPARTMENT OF SPACE)

Bangalore, the 12th September, 1975

S.O. 4817.—In accordance with the proviso to Rule-45 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Department of Space hereby exempt Engineering Services Division, Space Applications Centre, Ahmedabad, Services Facilities Division, Vikram Sarabhai Space Centre, Thumba, Services Facilities Division SHAR Centre at Sriharikota and the Civil Engineering Division of the Department of Space through its units all over India under the following terms and conditions from the operation of the Rule-45(1) of the Indian Electricity Rules, 1956, insofar as it relates to the execution of works to be carried out by the Electrical Contractor licenced by the State Government.

Works exempted are additions, alterations and also new works of all electrical installations irrespective of any voltage limits.

The electrical installations will be carried out under the direct supervision of a qualified and competent Electrical Engineer and shall be carried out by qualified and competent tradesman.

Immediately after completion of any installation which has been carried out departmentally, the Electrical Engineer under whose supervision the work has been carried out should certify that the work has been carried out satisfactorily in total conformity with the Indian Electricity Rules, 1956 before the electrical installations are energised.

[No. 5/11(5)/75-II]

N. S. ACHARYA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

परिवार नियोजन विभाग

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4818.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग की अधिसूचना सं० एफ० 1-26/67 स्थापना-1 (प० नि०), दिनांक 4 अगस्त, 1971 में प्रकाशित प्रधान (जन शिक्षा एवं प्रचार) भर्ती नियम, 1971 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का नाम परिवार नियोजन विभाग, प्रधान (जनशिक्षा एवं प्रचार) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिवार नियोजन विभाग, प्रधान (जन शिक्षा एवं प्रचार) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची के कालम 11 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि कर दी जाये:—

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:

केन्द्रीय सूचना सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ वेतनमान में दो वर्ष की सेवा की हो अथवा प्रचार मीडिया अधिकारियों के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधीन इन पदों पर 1300-50-1700 के वेतनमान अथवा समकक्ष वेतनमान में कम से कम 4 वर्ष तक सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि,—

साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं)"।

[सं० एफ० 1-26/67-स्थापना I]

सर्वेश्वर झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 22nd October, 1975

S.O. 4818.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Family Planning, Chief (Mass Education Media) Recruitment Rules, 1971, published in the Government of India, Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) Notification No. F. 1-26/67-Estt. I, dated 4th August, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Family Planning Chief (Mass Education and Media) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Family Planning Chief (Mass Education Media) Recruitment Rules, 1971 in column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"**Transfer on deputation.**—Officers of the senior scale of Junior Administrative Grade of the Central Information Service with two years service in the senior scale of Publicity/Media Officers with at least 4 years' service in the posts in the pay scale of Rs. 1300-50-1700 or equivalent under the Central Government (Period of deputation— ordinarily not exceeding 4 years)".

[No. F. 1-26/67-Estt. I.]

SARVESHWAR JHA, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4819.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नियम 38 के खंड (क) और उक्त नियमों की अनुसूची II के खंड "ख" में निर्दिष्ट छात्र पाइलट अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिये उपाध्यक्ष, राजस्थान फ्लाइंग क्लब/ग्लाइडिंग विंग, जयपुर के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, जयपुर, को प्राधिकृत करती है और 2 जनवरी, 1971 के भारत सरकार के राजपत्र के भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 34, दिनांक 16 दिसम्बर 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

"उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"4 प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, जयपुर"

[फा० सं० ए० वी०-11016/1/75-ए०/ए० आर०/1937(6)/1975]

एस० एकाम्बरम, उप-सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 4819.—In pursuance of the sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby authorises the Administrative Officer, Rajasthan Flying School, Jaipur, in place of the Vice-President, Rajasthan Flying Club/Gliding Wing, Jaipur, to grant or renew Student Pilot's Licence referred to in clause (a) of rule 38 and in section 'B' of Schedule II to the said rules, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 34, dated the 16th December, 1970, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd January, 1971, namely:—

In the said notification, for Serial No. 4 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"4. Administrative Officer, Rajasthan Flying School, Jaipur."

[F. No. Av. 11016/1/75-A/AR/1937(6)/1975]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4820.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सनन्द 1 और 33 से जी० जी० एस० एस० आई० पी० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहियें।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सनन्द 1 और 33 से जी० जी० एस० एस० आई० पी० तक पाईप-लाइन बिछाने के लिये

राज्य: गुजरात जिला मेहसाना तालुका: कालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सण्टीएर
1	2	3	4	5
जेथलाज	373/1	0	12	25
	372/1	0	08	60
	372/2	0	13	95
	355	0	03	88
	363	0	06	51
	363/2	0	04	19
	362/1	0	04	34
	357/1	0	29	92
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	475	0	04	96
	477/1	0	10	23
	477/2	0	08	22
	478/1/ए०	0	08	99
	478[1/सी०	0	08	84
	479/1/बी०	0	01	00
	480/1	0	04	42
	480/2	0	06	36
	487	0	01	40
	486	0	14	25
	483	0	01	00
	484	0	12	87
	कार्ट-ट्रेक	0	01	00
	550/2	0	11	00
	550/1	0	12	00
	545	0	18	91
	544	0	08	06
	10	0	04	50
	33/1	0	04	03
	12	0	09	07
	15	0	02	95
	11	0	00	50
	24/1	0	23	67
	24/2	0	07	86
	23/3	0	06	73
	23/2	0	05	65
	23/9	0	06	98
	23/4	0	02	14
	31	0	01	00
	32/1	0	07	44
	32/2	0	15	81
	44	0	13	33
	45	0	13	79
	48	0	09	00
	49	0	08	84
	50	0	20	30

[सं० 12016/16/75-ऐल० एंड एल]

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 21 October, 1975

S.O. 4820.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. Sanand I & 33 to GGS SIP in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the Land described in the Schedule annexed hereto

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For laying pipeline from Sanand 1 & 33 to G.G.S. SIP

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Jethlaj	373/1	0	12	25
	372/1	0	08	60
	372/2	0	13	95
	355	0	03	88
	363	0	06	51
	362/2	0	04	19
	362/1	0	04	34
	357/1	0	29	92
	Cart-track	0	01	00
	475	0	04	96
	477/1	0	10	23
	477/2	0	08	22
	478/1/A	0	08	99
	478/1/C	0	08	84
	479/1/B	0	01	00
	480/1	0	04	42
	480/2	0	06	36
	487	0	01	40
	486	0	14	25
	483	0	01	0)
	484	0	12	87
	Cart-track	0	01	00
	550/2	0	11	00
	550/1	0	12	00
	545	0	18	91
	544	0	08	06
	10	0	04	50
	13/1	0	04	03
	12	0	09	07
	15	0	02	95
	11	0	00	50
	24/1	0	23	67
	24/2	0	07	86
	23/3	0	06	73
	23/2	0	05	65
	23/9	0	06	98
	23/1	0	02	14
	21	0	01	00
	32/1	0	07	44
	32/2	0	15	81
	44	0	13	33
	45	0	13	79

1	2	3	4	5
	48	0	09	00
	49	0	08	84
	50	0	20	30

[No. 12016/16/75-L&L]

शुद्धि पत्र

का० आ० 4821.—पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला जामनगर तालुका जामनगर के लिये भारत के राजपत्र के भाग-11 खंड 3 (11) के पृष्ठ संख्या 2673 से 2764 तक दिनांक 26-7-75 को प्रकाशित का० आ० संख्या 2373 के द्वारा भारत सरकार, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12017/3/75-एल० एंड एल०/11 दिनांक 5-7-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़ें।

अनुसूची

तालुका : जामनगर जिला : जामनगर गुजरात: राज्य

के स्थान पर	पढ़ें
————	अलिया

[सं० 12017/3/75-एल० एंड एल०II]

ERRATUM

S. O. 4821.—In the schedule appended to the notification of the Government of India Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/3/75/L&L/II dt. 5-7-75 published vide S.O. No. 2373 dated 26-7-75 from page No. 2673 to 2674 of the Gazette of India Part II Section 3(ii) for Taluka Jamnagar Dist. Jamnagar Gujarat State, under Sub-Section (1) of Section 6 of the Petroleum pipelines (Acquisition of right of user in land). Act 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Taluka : Jamnagar Dist. : Jamnagar Gujarat State

For	Read
————	ALIA

[No. 12017/3/75-L&L/II]

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4822.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी ई एल से बी डी आर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी एस बी ई एल से बी डी आर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : कार्इरा तालुका : मातार

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ऐआरई	सेण्टीएर
गोबलेज	380/3	0	04	00
	380/4	0	02	50
	381/2	0	08	50
	382	0	18	00
	1	0	06	00
	3	0	06	00
	4/2	0	05	50
	13/2	0	05	50
	13/3	0	01	00
	14/1	0	03	25
	14/3	0	03	25
	17	0	05	50
	16	0	05	00
	463	0	00	50
	458/ए	0	04	75

[सं० 12016/17/75-एल० एण्ड एल०]

New Delhi, the 22nd October, 1975

S. O. 4822—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. BEL to BDR in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedules annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person OR by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from d.s. BEL to BDR

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi are
Coblage	380/3	0	04	00
	380/4	0	02	50
	381/2	0	08	50
	382	0	18	00
	1	0	06	00
	3	0	06	00
	4/2	0	05	50
	13/2	0	05	50
	13/3	0	01	00
	14/1	0	03	25
	14/3	0	03	25
	17	0	05	50
	16	0	05	00
	463	0	00	50
	458/A	0	04	75

[No. 12016/17/75-L&L]

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4823.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 124 तारीख 26-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

लक्वा ग्रुप गैदरिंग स्टेशन नं० 2 से लक्वा ग्रुप गेदरिंग स्टेशन नं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुका : सिलाकुटी

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ऐआरई	सेण्टी ए आर ई
सोला चाह् बगीचा	63 खा	0	12	04
	64 खा	0	1	34

[सं० 12016/18/74-एल० एण्ड एल०]

New Delhi, the 23rd October, 1975

S.O. 4823.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 124 dated 26-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specfied in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Lakwa Group Gathering Station No. 2 to Lakwa Group Gathering Station No. 1

State : Assam Distt. : Sibsagar Taluk : Silakuti

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Sola Chah Bagicha	63 Kha	0	12	04
	64 Kha	0	1	34

[No. 12016/18/74-L&L]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4824.—यत: पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1755 तारीख 7-6-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उन भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका: दसक्रोई जिला : अहमदाबाद गुजरात : राज्य

गांव	सर्वेक्षण नं०	तक		
		एच	ए	वर्गमील
जेतलपुर	281	0	02	56

[सं० 12017/7/74-एल० एण्ड एल०]

New Delhi, the 30th October, 1975

S. O. 4824—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of of Petroleum) S.O. No. 1755 dated 7-6-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to the notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Daskroi Dist. : Ahmedabad Gujarat : State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq.M.
Jetalpur	281	0	02	56

[No. 12017/7/74-L&L]

का० आ० 4825.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 177 तारीख 27-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी जी एस II से सी टी एफ तक पाइपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका: कालोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टेयर	ऐआरई	सेण्टी ऐआरई
सैज	712/पी	0	01	90
	700/1	0	13	30
	वी पी कैन्स	0	01	15
	696/2	0	05	70
	696/1	0	15	77
	697	0	09	05
	699	0	14	25
	1212	0	11	40
	1216	0	11	21
	1210/2	0	01	70
	1210/1	0	04	00
	वी पी कैन्स	0	01	90
	993	0	18	00
	वी पी	0	20	00
	978/2	0	02	00
	980	0	15	00
	977	0	04	00
	976	0	19	00
	970	0	07	00
	971	0	00	50
	969	0	03	00

[सं 12016/7/74-एल० एण्ड एल०/III]

S. O. 4825.—Whereas by a notification of the Govt. of India the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 177 dated 27-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from GGS II to CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Saij	712/P	0	01	90
	700/1	0	13	30
	V.P. Kans.	0	01	15
	696/2	0	05	70
	696/1	0	15	77
	697	0	09	05
	699	0	14	25
	1212	0	11	40
	1216	0	11	21
	1210/2	0	01	70
	1210/1	0	04	00
	V.P. Kans.	0	01	90
	993	0	18	00
	V.P.	0	20	00
	978/2	0	02	00
	980	0	15	00
	977	0	04	00
	976	0	19	00
	970	0	07	00
	971	0	00	50
	969	0	03	00

[No. 12016/7/74-L&L/III]

का० आ० 4826.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 178 तारीख 27-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुएं नं० 34 कालोल से सी०टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैण्टीयर
धामसाना	204	0	04	27
	203	0	03	07
	199	0	38	30
	198	0	07	20
	197	0	15	15
	कार्ट-ट्रेक	0	02	55
	323	0	01	05
	कार्ट-ट्रेक	0	00	50
	326	0	23	12
	328	0	09	90
	329	0	05	85
	330	0	05	55
	कार्ट-ट्रेक	0	01	05
	721	0	01	80
	720	0	06	23
	719/पी	0	12	68
	718	0	12	02
	716	0	04	20
	715	0	13	73
	701	0	04	35
	कार्ट-ट्रेक	0	00	50
	700	0	15	15
	731	0	01	00
	698	0	01	00
	697	0	07	05
	696	0	10	28
	कार्ट-ट्रेक	0	00	60
	803	0	14	17
	804	0	13	43
1	2	3	4	5
	810	0	12	75
	811	0	05	10
	612	0	06	75
	827	0	15	33
	766	0	12	60
	827	0	10	35
	829	0	17	36
	831	0	14	72
गांव कालोल	सर्वेक्षण नं०			
	251/48	0	53	06
	कार्ट-ट्रेक	0	01	24
	251/6	0	02	79
	251/5	0	20	61
	251/4	0	03	56
	कार्ट-ट्रेक	0	02	09
	251/66	0	11	32
	251/67	0	16	52
	251/68	0	12	32
	251	0	05	35
	251/143	0	05	27
	252/30	0	05	04
	252/32	0	10	00
	252/34	0	09	07
	252/37	0	15	04
	252/40	0	09	30
	252/43	0	15	97
	252/44	0	01	00
	252/42	0	08	06
	252/45	0	08	38
	252/95	0	17	36
	252/94	0	09	00
	कार्ट-ट्रेक	0	03	02
	252/172	0	11	70
	252/173	0	10	93
	252/174	0	01	00
	252/192	0	32	32
	252/194	0	01	00
	252/191	0	16	35
	252/190	0	14	89
	252/189	0	08	66
	252/200	0	05	50
	252/202	0	08	08
	कार्ट-ट्रेक	0	01	16
	252/307	0	08	37
	252/306	0	06	51

[सं० 12016/7/74-/एल०एंड एल०/4]

S.O. 4826.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 178 dated 27-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Well No. 34 Kalol to CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Dhamasana	204	0	04	27
	203	0	03	07
	199	0	36	30
	198	0	07	20
	197	0	15	15
	Cart-Track	0	02	55
	325	0	01	05
	Cart-Track	0	00	80
	326	0	23	12
	328	0	09	90
	329	0	05	85
	330	0	05	55
	Cart-Track	0	01	05
	721	0	01	80
	720	0	06	23
	719/P	0	12	68
	718	0	12	02
	716	0	04	20
	715	0	13	73
	701	0	04	35
	Cart-Track	0	00	50
	700	0	15	15
	731	0	01	00
	698	0	01	00
	697	0	07	05
	696	0	10	28
	Cart-Track	0	00	60
	803	0	14	17
	804	0	13	43
	810	0	12	75
	811	0	05	10
	812	0	06	75
	827	0	15	33
	766	0	12	60
	827	0	10	35
	829	0	17	36
	831	0	14	72
Village : Kalol	Survey No.			
	251/48	0	53	06
	Cart-Tack	0	01	24
	251/6	0	02	79
	251/5	0	20	61
	251/4	0	03	56
	Cart-Track	0	02	09
	251/66	0	11	32
	251/67	0	16	52
	251/68	0	12	32
	251	0	05	35
	251/143	0	05	27
	252/30	0	05	04
	252/32	0	10	00
	252/34	0	09	07
	252/37	0	15	04
	252/40	0	09	30
	252/43	0	15	97
	252/44	0	01	00
	252/42	0	08	06
	252/45	0	08	38
	252/95	0	17	36
	252/94	0	09	00
	Cart-Track	0	03	02
	252/172	0	11	70
	252/173	0	10	93
	252/174	0	01	00
	252/192	0	32	32
	252/194	0	01	00
	252/191	0	16	35
	252/190	0	14	89
	252/189	0	08	66
	252/200	0	05	50
	252/202	0	08	08
	Cart-Track	0	01	16
	252/307	0	08	37
	252/306	0	06	51

[No. 12016/7/74-L&L-IV]

का॰आ॰ 4827—यत: पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का॰आ॰ सं॰ 180 तारीख 27-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कुंए सं० 120 (किज) से जी०जी०एस० 7 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : गांधी नगर तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वेक्षण सं०	हैक्टेयर	एआरई	सैण्टीयर
1	2	3	4	5
टिटोडा	597	0	07	67
	596	0	15	91
उवांसाद	1195/2	0	04	48
	1195/3	0	12	54
	1195/4	0	03	25
	1195/16	0	06	16
	1195/17 एण्ड 18	0	10	79
	1194/2	0	07	32
	1194/3	0	06	11
	1195/5	0	01	00
	1196	0	13	45
	1201/1	0	14	73
	1201/2	0	02	86
	1201/3	0	10	10
	1202	0	05	33
	1203	0	25	26
	1184/2	0	33	47
	1180/1	0	00	50
	1183/2	0	06	50
	1183/1	0	05	82
	कार्ट-ट्रैक	0	00	52
	1147/1	0	06	69
	1147/2	0	15	56
	1146	0	16	80
	1145	0	01	04
	कार्ट-ट्रैक	0	01	17
	1149/1	0	04	68
	कार्ट-ट्रैक	0	00	52
	1109/1	0	12	98
	1108	0	03	00
	1107	0	04	16
	1110	0	04	16

[सं० 12016/7/74-एल०एण्डएल०/6]

टी० पी० सुब्रह्मनियन, अवर सचिव

S.O. 4827.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 180 dated 27-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For laying Pipeline from Well No. 120 (KIZ) to GGS-VII

State : Gujarat District Gandhinagar Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Titoda	597	0	07	67
	596	0	15	91
Uvarsad	1195/2	0	04	48
	1195/3	0	12	54
	1195/4	0	03	25
	1195/16	0	06	16
	1195/17 & 18	0	10	79
	1194/2	0	07	32
	1194/3	0	06	11
	1195/5	0	01	00
	1196	0	13	45
	1201/1	0	14	73
	1201/2	0	02	86
	1201/3	0	10	10
	1202	0	05	33
	1203	0	25	26
	1184/2	0	33	47
	1180/1	0	00	50
	1183/2	0	06	50
	1183/1	0	05	82
	Cart-Track	0	00	52
	1147/1	0	06	69
	1147/2	0	15	56
	1146	0	16	80
	1145	0	01	04
	Cart-Track	0	01	17
	1149/1	0	04	68
	Cart-Track	0	00	52
	1109/1	0	12	98
	1108	0	03	00
	1107	0	04	16
	1110	0	04	16

[No. 12016/7/74-L&-L/VI]

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4828.—यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र मेहसाना में व्यधन एन०के० 56 से जी०जी०एस० काढी-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 14-5-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब अत: पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी

उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

एन०के० 56 से जी०जी०एस० कादी-1 तक पाइप लाइन की प्रक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
1	2	3	4	5
पेट्रोलियम और रसायन	सूरज चलासन	2367	14-9-74	14-5-74

[सं० 12016/4/75-एल०एंड एल०/1]

New Delhi, the 27th October, 1975

S.O. 4828.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. NK 56 to GGS Kadi-1 in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 14-5-74.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation, referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from NK-56 to GGS Kadi-I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette India	Date of termination of operation
Petroleum & Chemicals	Suraj Chalasan	2367	14-9-74	14-5-75

[No. 12016/4/75-L&L/1]

का० आ० 4829.—यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र मेहसाना में ब्यधन एस० सी० बी० से शोभासन जी० जी० एस०-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 30-4-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब अत: पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

एस०सी०बी०, शोभासन से जी०जी० एस०-1 तक पाइप लाइन की प्रक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
1	2	3	4	5
पैट्रोलियम और रसायन	कदवासन हेबुवा	118	11-1-75	30-4-74

[सं० 12016/4/75-एल०एंड एल०/2]

S.O. 4829.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) At 1962 the Righ' of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. SCB to Sobhasan in GGS-I Mehsana oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 30-4-74.

Now, therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipelines from D.S. SCB to Solehasan GGS-I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum & Chemicals	Kadvasan Hebuva	118	11-1-75	30-4-74

[No. 12016/4/75/L&L II]

का० आ० 4830.—यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमिमें उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र मेहसाना में ब्यधन एन०के०-72 से जी०जी०एस० कादी-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 23-6-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

एन०के०-72 से जी०जी०एस० कादी-1 तक पाइप लाइन की प्रक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
1	2	3	4	5
पैट्रोलियम और रसायन	सूरजचलासन	2369	14-9-74	23-6-74

[सं० 12016/4/75-एल०एण्ड एल०/3]

S. O. 4830.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acguisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. NK-72 to GGS-Kadi-I in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-6-74.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from NK-72 to GGS-Kadi-I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation.
Petroleum & Chemicals	Suraj Chalasan	2369	14-9-74	23-6-74

[No 12016/4/75-L & L/III]

का० आ० 4831.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र मेहसाना में व्यधन एन० के०-55 से जी०जी०एस० कादी-1 तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 23-6-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

एन०के०-55 से जी०जी०एस० कादी-1 तक पाइप लाइन की प्रक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
1	2	3	4	5
पैट्रोलियम और रसायन	सूरज चलासन	2368	14-9-74	23-6-74

[सं० 12016/4/75-एल०एंड एल०/4]

S. O. 4831.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. NK-55 to GGS-Kadi-I in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-6-74.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from NK-55 to GGS-Kadi-1

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum & Chemicals	Suraj Chalasan	2368	14-9-74	23-6-74

[No. 12016/4/75-L & L/IV]

का० आ० 4832.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र कलोल में व्यधन सी० टी० एफ० कलोल से सी०टी०एफ०/जी०जी० एस नार्थ कादी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 7-11-1974 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

सी०टी०एफ कलोल से सी०टी०एफ/जी०जी०एस नार्थ कादी तक पाइप लाइन की प्रक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम और रसायन	सूरज चलासन	850	30-3-1974	7-11-1974

[सं० 12016/4/75-एल०एण्ड एल०/V]
के० वी० देशपांडे,
गुजरात के लिये अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 4832—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from C.T.F. Kalal to C.T.F./G.G.S. North Kadi in Kalol oil field in Gujarat State.

2. And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-sections (1) of section 7 of the said act on 7-11-1974.

3. Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipelines from CTF Kalol to CTF/GGS North Kadi

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination
Petroleum & Chemicals	Suraj Chalasan	850	30-3-74	7-11-74

[No. 12016/4/75-L & L/V]
K.V. DESHPANDE, Competent Authority under the Act for Gujarat

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1975

का० आ० 4833.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में टेलिकाम फैक्ट्री, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या टेलिकाम फैक्ट्री, देवनार, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र की, श्री एस० ए० गैकवाड मोटर चालक को कथित दुर्घटना करने के 3-1/4 वर्ष बाद सेवा से हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो श्री एस० ए० गैकवाड किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल-40011(6)/74-एल० आर०-3/डी 2(बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1975

S.O. 4833.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Telecom Factory, Bombay, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer he said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Telecom Factory, Deonar, Bombay, in removing Shri S. A. Gaikwad. Motor Driver, from service after 3-1/4 years of the alleged commission of the accident is justified? It not, to what relief is Shri S. A. Gaikwad entitled?

[No. L-40011(6)/74-LR. III/D. 2(B)]

आदेश

का० आ० 4834.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एयर इंडिया, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या एयर इंडिया के प्रबन्धतंत्र की, एयर इंडिया के फ्लाइट पर्सर-श्री औबरे डीसिलवा को सेवाएं 12 अप्रैल, 1965 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-11011(17)/73-एल०आर०-3/डी० 2(बी)]

ORDER

S.O. 4834.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Air India, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Air India in terminating the services of Shri Aubrey Desylva, Flight Purser of Air India with effect from the 12th April, 1965, was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 11011(17)/73-LR. III/D. 2(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

का० आ० 4835.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेल के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ओम पाल चोपड़ा, मुख्य ट्रेन निरीक्षक, पश्चिमी रेल, कोटा को कोई वित्तीय हानि इस कारण उठानी पड़ी कि प्रबन्धतंत्र ने उक्त कर्मकार द्वारा 3-7-1959 से 29-2-1960 तक की अवधि के बारे में, जिसके दौरान एक अन्य कर्मकार श्री फूल सिंह को स्थानापन्न मुख्य टिकट कलक्टर के रूप में कार्य करने के लिये गलत तौर पर अनुज्ञात किया गया था, दावा किया गया वेटेज देने से इन्कार कर दिया? यदि हां, तो श्री ओमपाल चोपड़ा किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल-41011/17/73-एल० आर०-3/डी० 2बी]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4835.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway and their workmen in respect of the matter specified in he Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether Shri Om Pal Chopra, Chief Train Inspector, Western Railway, Kota, suffered any monetary loss on account of the refusal of the management to grant weightage claimed by the said workman in respect of the period 3-7-1959 to 29-2-1960 during which another workman, Shri Phool Singh was wrongly allowed to officiate as Head Ticket Collector? If so, to what relief is Shri Om Pal Chopra entitled?

[No. L-41011/17/73-LR. III/D. IIB]

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1975

का० आ० 4836.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धतंत्र की, श्री आर० एस० ग्रेवाल, फ्लाइट स्टीवर्ड को 28 अगस्त, 1974 से सेवा से हटाने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 11012(4)/75-डी० 2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4836.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Airlines and their workmen in respect of the mattes specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Indian Airlines in removing Shri R. S. Grewal, Flight Steward, from service with effect from 28-8-1974, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 11012(4)/75-D. II(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर 1975

का० आ० 4837.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स फतवाह-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, धनबाद को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स फतवाह-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की, श्री गुपुत को 28-5-75 से ट्राली मैन के पद से चौकीदार के पद पर, श्री बालक दास को 26-5-75 से गैंग खलासी के पद से की-मैन के पद पर और श्री लखन को 26-5-75 से की-मैन के पद से मेट के पद पर प्रत्यावर्तित करने की कार्रवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं।

[संख्या एल-41011(3)/75-डी० 2(बी)]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 4837.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Futwah-Islampur Light Railway Company Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), he Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Futwah-Islampur Light Railway Company Limited in reverting Shri Guput from the post of Trollyman to the post of Chowkidar with effect from 28-5-1975, Shri Balak Das from the post of Gang Khalasi to the post of Keyman with effect from 26-5-1975, and Shri Lakhan from the post of Keyman to the post of Mate with effect from 26-5-1975, is justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?

[No. L. 41011(3)/75-D. II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

का० आ० 4838.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री एम० सी० कोन्नुर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लम्बित हैं;

और उक्त श्री एम० सी० कोन्नुर की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रह गई हैं;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भागवत होंगे, जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा, और श्री एम० सी० कोन्नुर के समक्ष लम्बित उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त कार्यवाहियों के निपटाने के लिये श्री जी० एस० भागवत, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर को इस निर्देश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों पर और आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा, जिस पर वे उसे स्थानान्तरित की जायें, और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक न्यायाधिकरण की निर्देश संख्या और तारीख
1	2	3
1.	कनारा बैंकिंग कारपोरेशन, मंगलौर के कर्मकार और प्रबन्धतन्त्र।	संख्या 23/87/69-एल०आर०-3 तारीख 17 दिसम्बर, 1969.
2.	प्रीमियर इंश्योरेंस कं० लि०, मैसूर के कर्मकार और प्रबन्ध-तंत्र।	संख्या 40/75/10-एल०आर०-1 तारीख 15 मई, 1970.

1	2	3
3.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-29011/14/71-एल०आर-4 तारीख 22/24 जून, 1971.
4.	विजय बैंक लि०, बंगलौर-1 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-12012/19/73-एल० आर-3, तारीख 21 मार्च, 1973.
5.	मैसर्स डालमिया सीमेण्ट (भारत) लि०, हौस्पेट के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-29012/12/73-एल०आर-4, तारीख 29 मई, 1973.
	विजय बैंक लि०, बंगलौर-1 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-12012/58-73-एल० आर०-3, तारीख 16 जून, 1973.
7	मैसर्स तुंगाभद्रा मिनरल्स (प्रा०) लि०, तारानगर, डाकघर, सांदुर तालुक, बेल्लारी जिला ।	संख्या एल-29011/40/73-एल०आर०-4 तारीख 29 सितम्बर, 1973.
8.	मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, होस्पेट की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के रेजिंग ठेकेदार, श्री ई० कुप्पिस्वामी के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच ।	संख्या एल-26012/6/73-एल०आर-4(ii) तारीख 14 जनवरी, 1974.
9.	मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, होस्पेट की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के रेजिग ठेकेदार, श्री एम० रामन् के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच ।	संख्या एल-26012/6/73-एल०आर-4(i), तारीख 14 जनवरी, 1974.
10.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच ।	संख्या एल-12025/20/72-एल० आर-3, तारीख 10 जनवरी, 1974.
11.	मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल, होस्पेट, जिला बेल्लारी के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-29012/5/74-एल० आर-4, तारीख 23 अप्रैल, 1974.
12.	मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, होस्पेट, जिला बेल्लारी के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26011/8/74-एल० आर०-4, तारीख 21 अक्तूबर, 1974.
13.	मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, होस्पेट, जिला बेल्लारी के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26014/12/74-एल० आर-4, तारीख 25 अक्तूबर, 1974.
14.	मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, होस्पेट, बेल्लारी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26012/4/74-एल० आर 4, तारीख 15 नवम्बर, 1974.
15.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, भद्रावती के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26011/7/74-एल० आर-4, तारीख 21 नवम्बर, 1974.
16.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, भद्रावती के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26011/8/74-एल० आर-4, तारीख 21 नवम्बर, 1974.
17.	मैसर्स डालमिया इन्टरनैशनल होस्पेट, बेल्लारी जिला की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26011/8/74-एल० आर-4, तारीख 21 दिसम्बर, 1974.
18.	मैसर्स डालमिया इन्टरनैशनल, होस्पेट, बेल्लारी जिला की बी० आर० एच० लौह अयस्क खानों के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26012/6/74-एल० आर-4, तारीख 10 जनवरी, 1975.
19.	मैसर्स डालमिया इन्टरनैशनल, होस्पेट की भारत रायाना हुरुवा लौह अयस्क खानों के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-26011/13/74-एल० आर० 4, डी-2(बी), तारीख 27 जनवरी, 1975.
20.	भारत गोल्ड माइन्स लि०, अरगाम, के०एफ०जी० के कर्मकार और प्रन्धतंत्र ।	संख्या एल-29012/9/74-एल० आर-4, डी० ओ-3 (बी), तारीख 26 फरवरी, 1975.
21.	भारत गोल्ड माइन्स लि० अरगाम के०जी०एफ० के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-29012/25/74-एल० आर-4/डी-4, (बी), तारीख 3 मार्च, 1975.
22.	मैसर्स सांदुर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स (प्रा०) लि०, यशवंत नगर, बेल्लारी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-27011/4/74-एल० आर-4/डी-4(बी), तारीख 4 मार्च, 1975.
23.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।	संख्या एल-29011/15/74-एल० आर-4

तारीख, 30 जनवरी, 1975

[संख्या एल-26012/6/73-एल० आर-4/डी-4 (बी)]

ORDER

Dated New Delhi, the 21st July, 1975

S. O. 4838.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri M.C. Konnur, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore;

And whereas the services of the said Shri M.C. Konnur, are no longer available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G.S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore, withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before Shri M. C. Konnur and transfers the same to Shri G.S. Bhagwat, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference number and date of the Industrial Tribunal
1	2	3
1.	Workman and the Management of Canara Banking Corporation, Mangalore.	No. 23/87/69-LR. III dated the 17th December, 1969.
2.	Workmen and the Management of Premier Insurance Co. Ltd., Mysore.	No. 40/15/70-LR. I dated the 15th May, 1970.
3.	Workmen and the Management of Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravati.	No. L-29011/14/71-LR-IV dated 22/24th June, 1971.
4.	Workmen and the Management of Vijaya Bank Ltd., Bangalore-1.	No. L-12012/19/73-LR. III dated the 21st March, 1973.
5.	Workmen and the management of M/s Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Hospet.	No. L-29012/12/73-LR. IV dated the 29th May, 1973.
6.	Workmen and the management of Vijaya Bank Ltd., Bangalore-1.	No. L-12012/58/73-LR. III dated the 16th June, 1973.
7.	Workmen and the Management of M/s Tungabhadra Minerals (P) Ltd. Taranagar P.O. Sandur Taluk, Bellary Dt.	No. L-29011/40/73-LR. IV dated the 29th September, 1973.
8.	Between the management of Sri E. Kuniswamy, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s Dalmia International, Hospet and their workmen.	No. L-26012/6/73-LR. IV (ii) dated the 14th January, 1974.
9.	Between the management of Sri M. Raman, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet and their workmen.	No. L-26012/6/73-LR. IV (i) dated the 14th January, 1974.
10.	Between the employers in relation to the Reserve Bank of India and their workmen.	No. L-12025/20/72-LR. III dated the 10th January, 1974.
11.	Workmen and the managerment of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-29012/5/74-LR-IV dated the 23rd April, 1974.
12.	Workmen and the management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-26011/8/74-LR. IV dated the 21st October, 1974.
13.	Workmen and Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-26014/12/74-LR. IV dated the 25th October, 1974.
14.	Workmen and the management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-26012/4/74-LR. IV dated the 15th November, 1974.
15.	Workmen and Management of Mysore Iron and Steel Co. Ltd., Bhadravati.	No. L-26011/7/74-LR. IV dated the 21st November, 1974.
16.	Workmen and the management of Mysore Iron & Steel Co. Ltd., Bhadravati.	No. L-26011/8/74-LR. IV dated the 21st November, 1974.
17.	Workmen and Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-26011/8/74-LR IV dated the 21st December, 1974.
18.	Workmen and Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.	No. L-26012/6/74-LR. IV dated the 10th January, 1975.
19.	Workmen and Management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet.	No. L-26011/13/74-LR. IV D. 2(B) dated the 27th January, 1975.
20.	Workmen and Management of Bharat Gold Mines, Ltd. Oorgam, K.G.G.	No. L-29012/9/74-LR. IV D.O. 3(B) dated the 26th Feburary, 1975.
21.	Workmen and Management of Bharat Gold Mines Ltd. Oorgam, K.G.F.	No. L-29012/25/74-LR. IV/D-IV (B) dated the 3rd March, 1975.
22.	Workmen and Management of M/s. Sandur Manganese & Iron Ores (P) Ltd., Yashwantnagar, Bellary Distt.	No. L-27011/4/74-LR-IV/D-IV (B) dated the 4th March, 1975.
23.	Workmen and Management of Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravati.	No. L-29011/15/74-LR. IV dated the 30th January, 1975.

[No. L-26012/6/73-LR. IV/D-IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4839.—यतः भिलाई स्टील प्लांट (माइन्स) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त खदान मजदूर संघ, नन्दिनी माइन्स करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त प्रबन्ध और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्तियों के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 17 अक्तूबर, 1975 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. श्री वी० पी० जयाकुमार, उप कार्मिक प्रबन्धक (खान), भिलाई स्टील प्लांट।
2. श्री आर० पी० सिंह, सहायक कार्मिक प्रबन्धक, (आई० आर०); भिलाई स्टील प्लांट।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. श्री सी० आर० बक्शी, सहायक महा सचिव, एस० के० एम० एस० (एटक), (संयुक्त खदान मजदूर संघ) (एटक)।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, निदेशक (कार्मिक), सैल, नई दिल्ली के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है :—

(1) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय : "क्या भिलाई स्टील लिमिटेड की कैप्टिव माइन्स में खनन संक्रियाओं में रत ठेकेदारों और श्रम सहकारियों के अधीन नियोजित कर्मकारों को उसी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये जो कि दिनांक 13-11-1973 के समझौते के अनुसरण में स्टील प्लांट की कैप्टिव माइन्स के सीधे नियोजित कर्मचारियों को 1973-74 वर्ष में किया गया था। यदि हां, तो क्या भुगतान उक्त सीधे कर्मचारियों के सम मूल्य पर होना चाहिए या किसी अन्य दर पर ?

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है : भिलाई स्टील प्लांट (खान) का प्रबन्धतंत्र, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई-1, जिला दुर्ग (म० प्र०)

(3) श्रमिक का नाम यदि वह विवाद में स्वयं अन्तर्ग्रस्त हो, या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम : संयुक्त खदान मजदूर संघ (एस० के० एम० एस०) (एटक) खानों में मान्यता प्राप्त संघ, पंजी० सं० 412, नन्दिनी माइन्स, जिला दुर्ग (म० प्र०)

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या :

सीधे	अप्रत्यक्ष (ठेके संबंधी श्रम सह०)
7908	8774

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :

8774

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :
ह०/- (वी० पी० जयाकुमार) उप कार्मिक प्रबन्धक (खान)	ह०/- (सी० आर० बक्शी) सहायक महा सचिव।
ह०/- (आर० पी० सिंह) सहायक कार्मिक प्रबन्धक (खान)	(एस के० एम० एस०) (एटक), संयुक्त खदान मजदूर संघ।

स्वीकार किया

हस्त०/-

(आर० पी० बिल्लिमोरिया)

निदेशक (कार्मिक)

सैल

नई दिल्ली।

साक्षी :

1. ह०/- अपाठ्य
2. ह०/- अपाठ्य

[संख्या एल-26013/3/75-डी०-4(बी०)-(i)]

ORDER

New Delhi, the 28th October, 1975

S.O. 4839.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhilai Steel Plant (Mines), Hindustan Steel Limited, Bhilai and their workmen represented by Samyukat Khadan Mazdoor Sangh, Nandini Mines;

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 17th October, 1975.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties

Representing Employer

1. Shri V.P. Jayakumar, Dy. Personnel Manager (Mines), Bhilai Steel Plant.
2. Shri R.P. Singh, Asstt. Personnel Manager (IR), Bhilai Steel Plant.

Representing Workmen

1. Shri C.R. Bakshi, Asstt. General Secretary, S.K.M.S. (AITUC) (Samyukta Khadan Mazdoor Sangh) (AITUC).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri R.P. Billimoria, Director (Personnel), SAIL, New Delhi.

(i) Specific Matters in Dispute :

"Whether the workmen employed under the Contractors and Labour Co-operatives engaged in mining operations in the Captive Mines of Bhilai Steel Plant should be paid the reward which was paid to the direct employees of the Captive Mines of Bhilai Steel plant in the Year 1973-74 in pursuance of the settlement dated 13-11-1973. If so, whether the payment should be at par with the said direct employees or at any other rate."

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and addresses of the establishment or undertaking involved :

The Management of Bhilai Steel Plant (Mines), Hindustan Steel Limited, Bhilai-1, Distt. Durg. (M.P.)

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workmen in question :

Samyukta Khadan Mazdoor Sangh. (S.K.M.S.) (AITUC) Recognised Union in Mines, Reg. No. 412, Nandini Mines, Distt. Durg (M.P.).

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking effected :

Direct	Indirect (Contractual/Labour Coop).
7908	8774

(v) Estimated number of workmen effected or likely to be effected by the dispute :

8774

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties :

Representing Employer :	Representing Workmen :
Sd/-	Sd/-
V. P. Jayakumar,	C. R. Bakshi,
Dy. Personnel Manager (Mines)	Asstt. General Secretary SKMS (AITUC) Samyukta Khadan Mazdoor Sangh
Sd/-	
R. P. Singh,	
Asstt. Personnel Manager (Mines)	

Accepted

Sd/-

R. P. Billimoria

Director (Personnel)

SAIL

New Delhi

Witness :

1. Sd/- Illegible.
2. Sd/- Illegible.

[No. L-26013/3/75-DJV(B)-(i)]

आदेश

का० आ० 4840.—यत: भिलाई स्टील प्लान्ट (माइन्स), हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व मेटल माइन्स वर्कर्स यूनियन, नन्दिनी और भिलाई स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कामगर संघ, नन्दिनी करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: उक्त प्रबन्धतंत्र और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 17 अक्तूबर, 1975 को मिला था, प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :
1. श्री वी० पी० जयकुमार, उपकार्मिक प्रबन्धक (खान), भिलाई स्टील प्लान्ट।
2. श्री आर० पी० सिंह, सहायक कार्मिक प्रबन्धक (आइ आर), भिलाई स्टील प्लान्ट।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. श्री जी० पी०, शुक्ला, सचिव, एम० एम० डबल्यु० यू० (मेटल-माईन्स वर्कर्स यूनियन), नन्दिनी।
2. श्री पी० एन० सिंह, सचिव, बी एस एण्ड ई के एस, (भिलाई स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कामगर संघ), नन्दिनी।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० पी० बिलिमोरिया, निदेशक (कार्मिक), सेल, नई दिल्ली के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

"क्या भिलाई स्टील प्लांट की कैप्टिव माइन्स के खनन कार्यों में लगे ठेकेदारों और श्रम सहकारियों के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को वे पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो दिनांक 13-11-1973 के समझौते के अनुसरण में भिलाई स्टील प्लांट की कैप्टिव माइन्स में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को वर्ष 1973-74 में दिया गया था। यदि हां, तो क्या भुगतान उक्त सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के सममूल्य पर होना चाहिए या किसी अन्य दर पर।"

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है :

भिलाई स्टील प्लांट (माइन्स) का प्रबन्धतंत्र,
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,
भिलाई I,
जिला दुर्ग (एम० पी०) ।

(3) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम :

एम० एम० डबल्यु० यू० (मेटल माइन्स, वर्कर्स (यूनियन) पंजीकृत संघ, नन्दिनी ।	भिलाई स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कामगर संघ (बी एस एण्ड ई के एस) पंजीकृत संघ, नन्दिनी ।

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या :

सीधे	अप्रत्यक्ष (ठेका संबंधी/श्रम सहकारी)
7908	8774

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :

8774

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :
ह०/- वी० पी० जयकुमार,	ह०/- जी० पी० शुक्ला,
उप कार्मिक प्रबन्धक (खान)	सचिव, एम० एम० डबल्यु० यू० (मेटल माइन्स वर्कर्स यूनियन), नन्दिनी ।
ह०/- आर० पी० सिंह,	ह०/- पी० एन० सिंह,
सहायक कार्मिक प्रबन्धक (खान)	सचिव, बी० एस० एण्ड ई के एस (भिलाई स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कामगर संघ), नन्दिनी ।

स्वीकृत

ह०/- आर० पी० बिल्लिमोरिया, निदेशक (कार्मिक) सेल, नई दिल्ली ।

साक्षी :

1. ह०/- अपाठ्य
2. ह०/- अपाठ्य

[संख्या एल-26013/3/75-डी-4(बी०)-(ii)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 4840.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhilai Steel Plant (Mines), Hindustan Steel Limited, Bhilai and their workmen represented by Metal Mines Workers Union, Nandini and Bhilai Steel and Engineering Kamgar Sangh, Nandini:

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentinoned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 17th October, 1975.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947).

BETWEEN

Name of the parties :

Representing Employer :

1. Shri V. P. Jayakumar, Dy. Personnel Manager (Mines), Bhilai Steel Plant.
2. Shri R.P. Singh, Asstt. Personnel Manager (IR), Bhilai Steel Plant.

Representing Workmen :

1. Shri G.P. Shukla, Secretary, M.M.W.U. (Metal Mines Workers' Union) Nandini.
2. Shri P. N. Singh, Secretary, BS & EKS. (Bhilai Steel & Engineering Kamgar Sangh) Nandini.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri R. P. Billimoria, Director (Personnel), SAIL, New Delhi.

(i) Specific matters in Dispute :

"Whether the workmen employed under the Contractors and Labour Co-operatives engaged in mining operations in the Captive Mines of Bhilai Steel Plant should be paid the reward which was paid to the direct employees of the Captive Mines of Bhilai Steel Plant in the year 1973-74 in pursuance of the settlement dated 13-11-1973. If so, whether the payment should be at par with the said direct employees or at any other rate."

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and addresses of the Establishment or Undertaking Involved :

The Management of
Bhilai Steel Plant (Mines),
Hindustan Steel Limited,
Bhilai-1,
Distt. Durg. (M.P.).

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen in question :

M. M. W. U. (Metal Mines) Workers' Union) Registered Union, Nandini.	Bhilai Steel & Engg. Kamgar Sangh (BS & EKS) Registered Union, Nandini.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking effected :

Direct	Indirect (Contractual/ Labour Coop).
7908	8774

(v) Estimated number of workmen effected or likely to be effected by the dispute :

8774

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties :

Representing Employer :

Sd/-
V. P. Jayagumar,
Deputy Personnel Manager
(Mines)

Representing Workmen :

Sd/-
G. P. Shukla,
Secretary, M. M. W. U.
(Metal Mines Workers' Union)
Nandini.

Sd/-
R. P. Singh,
Asstt. Personnel Manager (Mines)

Sd/-
P. N. Singh,
Secretary, BS & EKS.
(Bhilai Steel & Engg.
Kamgar Sangh), Nandini.

Accepted

Sd/-
R. P. Billimoria
Director (Personnel)
SAIL
New Delhi.

Witness :

1. Sd/- Illegible.
2. Sd/- Illegible.

[No. L-26013/3/75-D-IV-(B)-(ii)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.).

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

का० आ० 4841.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मद्रास स्टीविडोअर्स एसोसिएशन, मद्रास-1 से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है—

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानिअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मद्रास स्टीविडोअर्स एसोसिएशन का, श्री ई० जी० जॉनसन, निम्न श्रेणी लिपिक की सेवाएं 23-7-1973 से समाप्त करना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-33012/1/75/डी-4 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 24th July, 1975

S.O. 4841.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the Madras Stevedores Association, Madras-1 and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the Madras Stevedores' Association was justified in terminating the services of Shri E. G. Johnson, Lower Division Clerk, with effect from 23-7-1973? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-33012/1/75/D-IV (A)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

का० आ० 4842.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इससे उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मोर्मुगाओ बन्दरगाह (गोवा) स्थित 12 स्टीविडोअर्स के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची-1

1. मैसर्स एजेंसिया कोमर्शियल मेरिटिया, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

2. मैसर्स एजेंसिया अल्ट्रामैरिना प्राइवेट लिमिटेड, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

3. मैसर्स चौगुले ब्रदर्स, मोर्मुगाओ बन्दरगाह (गोवा)।

4. मैसर्स दामोदर मंगलजी एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

5. मसर्स ऐलेस्बाओ पेरीरा एण्ड सन्स, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

6. मैसर्स मचाडो एण्ड सन्स, एजेंट्स एण्ड स्टीविडोअर्स प्राइवेट लि० वास्को-ड-गामा (गोवा)।

7. मैसर्स गोसालिया शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, वस्को-ड-गामा (गोवा)।

8. मैसर्स लिया लिटाओ एण्ड कम्पनी, मोर्मुगाओ बन्दरगाह (गोवा)।

9 मैसर्स मोर्मुगाओ नावेगाडोरा लिमिटेड, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

10. मैसर्स राजाराम वी० रेदिज, वास्को-ड-गामा गोवा)।

11. मैसर्स वी० एम० सालगाँओकर एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, वास्को-ड-गामा (गोवा)।

12. मैसर्स वी० एस० डेम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मोर्मुगाओ बन्दरगाह (गोवा)।

अनुसूची-2

(क) क्या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मोर्मुगाओ बन्दरगाह के स्टीविडोअर्स का, श्री दिगम्बर नारायण हदफदकार, अस्थायी विचमैन (रजिस्ट्रीकरण संख्या 408-डी) को 8 अक्तूबर, 1974 से नियोजन देने से इनकार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-36012(1)/75-डी-4(ए)]

नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1975.

S.O. 4842.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of 12 Stevedores at Mormugoa Harbour (Goa) specified in the Schedule I annexed hereto and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule II hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE I

1. Messors Agencia Commercial Maritima, Vasco-da-Gama (Goa).
2. Messrs Agencia Ultramarina Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
3. Messrs Chowgule Brothers, Mormugoa Harbour (Goa).
4. Messrs Damodar Mangalji and Company (Private) Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
5. Messrs Elesbao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama (Goa).
6. Messrs Machado and Sons, Agents and Stevedores Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
7. Messrs Gosalia Shipping Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
8. Messrs Lima Leitao and Company, Mormugoa Harbour (Goa).
9. Messrs Mormugoa Navegadora Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
10. Messrs Rajaram V. Redij, Vasco-da-Gama (Goa).
11. Messrs V. M. Salgaocar and Brothers Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
12. Messrs V. S. Dempo and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa).

SCHEDULE II

(a) Whether the Stevedores of Mormugoa Harbour specified in Schedule I are justified in refusing employment to Shri Digamber Narayan Hadfadkar, Temporary Winchman, (Registration No. 408-D) with effect form the 8th October, 1974? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-36012(1)/75-D-IV (A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का० आ० 4843.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री काहन सिंह खान स्वामी कोटा की गुड्डा लम्बाखो और बोराबास बलुआ पत्थर खानों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री काहन सिंह, खान स्वामी सूरजपोल, कोटा का कोटा जिले में बोराबास बलुआ पत्थर खान और बुन्दी जिले में लम्बाखो और गुड्डा बलुआ पत्थर खान में नियोजित कर्मकारों की लेखा वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से लाभ साझेदारी बोनस के संदाय की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए कितने बोनस के हकदार हैं ?

[सं०-एल० 29011/108/75-डी-3 बी]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4843.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Gudda Lambakho and Borabas Sand Stone Mines of Shri Khan Singh Mine Owner, Kota, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Borabas Sand Stone Mines in Kota District and Lambhakho and Gudda Sand Stone Mines in Bundi District of Shri Khan Singh, Mine Owner, Surajpole, Kota for payment of Profit Sharing Bonus @ 20 per cent of wages for the accounting years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 is justified ? If not, to what quantum of bonus are the said workmen entitled for each of these years ?

[No. L-29011/108/75/DIII B]

New Delhi, the 26th October 1975

S.O. 4844— In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhandigund Lime stone Mines Kemmangundi Iron Ore Mines and Bilikabetta Quartzite Mines of Messrs Mysore Iron and Steel Company Limited Bhadravati and their workmen which was received by the Central Government on the 18th October, 1975.

BEFORE SHRI G.S. BHAGWAT, B.A., LLB., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Reference No. 7 of 1975 (Central)

I PARTY		II PARTY
Workmen represented by The General Secretary, Mysore Iron & Steel Ltd., Mines Employees' Association, Room No. 1 Trainees Block 10, New Colony, Bhadravathi, Shimoga District.	Vs	The General Manager, Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravathi.

PRESENT :

For the I Party—None present.

For the II Party—Sri V.L. Narasimha Murthy, Advocate, Bangalore.

ORDER OF REFERENCE

(Central Government Order No. L-29011/15/74-L. IV dated 30-1-1975).

AWARD

The Central Government, being of opinion, that an industrial dispute existed between the employes in relation to management of Bhandigund Lime Stone Mines, Kemmangundi Iron Ore Mines and Bilikalbetta Quartzite Mines of Messrs Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravathi and their workmen in respect of the matters specified in the schedule in exercise of the powers under Section 7-A and Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by their Order No. L-29011/15/74-L. IV dated 30-1-1975 constituted an Industrial Tribunal with Shri M.C. Konnur as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and referred the said dispute for adjudication on the matters specified in the schedule which are as follows :—

Whether the management of Messrs Mysore Iron and Steel Limited who are the lease holders of Bandigunda Lime Stone Mines is justified in not confirming and in not granting annual increments to the following seventeen employees (skilled workers) in spite of their continuous service for the last 7 to 8 years ? If not, to what relief are these employees entitled ?

1. Sri U. Karunakaran,	Operating Drilling
2. Sri P.T. Kochunni	Do.
3. Sri C.A. Ganeshan.	Do.
4. Sri Govinda Singh Lavoot	Do.
5. Sri P.N. Basavaraj	Skilled Workers
6. Sri Subbiah	Do.
7. Venkatesh .	Do.
8. Kariappa .	Do.
9. Subbaraj Urs.	Do.
10. Siromani .	Do.
11. Sri Armugam	Do.
12. Sri B.K. Subbaiah	Do.
13. Sri T.M. Thomas	Do.
14. Sri P. Rajan Nair	Do.
15. Sri T.G. Bhaskaran Achar	Do.
16. Sri P.G. George .	Do.
17. Sri Munirathanam Naidu	Do.

2. On receipt of the above Reference, the same came to be numbered as Ref. No. 7 of 1975 (Central) on the file of the Industrial Tribunal, Bangalore, and notices were issued to the parties on 11-4-75 for filing of statement of demands.

3. Workmen represented by the General Secretary, Mysore Iron & Steel Ltd., Mines Employees' Association, New Colony Bhadravathi, Shimoga District, (hereinafter called as the I Party) though duly served, did not choose to file the claim statement in support of their demand though sufficient and adequate opportunity was given to them. No statement of demand was also filed by the General Manager. Mysore Iron & Steel Limited, Bhadravathi, (hereinafter called as the II Party) and both the parties remained absent when called out on 26-7-1975. In the meanwhile, an Industrial Tribunal with Shri M.C. Konnur as Presiding Officer constituted to hear the above Reference, since retired, the case was adjourned to 26-7-1975 awaiting further notification by 25-8-1975. On 25-8-1975, again the case case was adjourned to 10-9-1975 awaiting further notification from the Central Government. On 10-9-1975, a common order No. L. 26012/6/73-LR-IV-D-IV (B) dated 21st July 1975 was received from the Central Government withdrawing the proceedings in relation to the above dispute from Sri M.C. Konnur, since retired and transferred the same to Sri G.S. Bhagawat as Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore, for the disposal of the proceedings from the stage at which they are transferred. Thereafter, notice was issued to the I party and also to the II Party as well to file statement of demands by 29-9-1975. On that day, Sri V.L. Narasimha Murthy, Advocate, appearing for the II Party filed I.A. No. 1 with annexure requesting to pass an Award in terms of Compromise Petition. He also furi ther submitted that the Compromise Petition was signed by Sr-M. Selvarajan, General Secretary of the I Party Union and the General Manager of the II Party and stated that they have no objection for an Award being passed in terms of the compromise arrived at between the workmen and the employer. The I Party, though duly served, remained absent when called.

4. Heard Sri V.L. Narasimha Murthy for the II Party and and I got myself satisfied that a compromise was entered into between the I Party-Workmen and the II Party in respect of the disputes covered under the above Reference and the terms of compromise are fair and reasonable and hence the same came to to be recorded. Later, on the same day, a letter was received from the Party by post stating that the case is favourably settled by the II Party-Management and requesting to accept the Joint Compromise Petition already sent by the II Party to be filed through their Advocates.

5. In the circumstances, the Joint Compromise Petition filed by Sri V.L. Narasimha Murthy has been accepted and the following Award is passed.

AWARD

An Award is passed in terms of the Joint Compromise Petition filed before this Tribunal on 29-9-75 which shall form part of this Award. No order as to costs.

(Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me).

Bangalore, 11th October, 1975

[No. L-29011/15/74-LR IV D. III B]

BEFORE THE PRINCIPAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, BANGALORE

Reference No. 7/1975 (Central)

First Party		Second Party
Workmen represented by the General Secretary, Mysore Iron and Steel Ltd., Mines Employees' Association, Room No. 1, Trainees' Block No. 10, New Colony, Bhadravathi, Shimoga District.	*Vs*	General Manager, Mysore Iron and Steel Ltd., Bhadravathi.

The First Party and Second Party referred to above file a a Compromise petition in the above said reference as follows :

The Industrial Dispute raised by the I Party against the II Party is referred to this Hon'ble Tribunal for adjudication on the following issues :

"Whether the management of Messrs. Mysore Iron and Steel Limited, who are the lease holders of Bhadigund Limestone Mines, Kemmangadi Iron Ore Mines and Bilikalbetta Quarzite Mines is justified in not confirming and in not granting annual increments to the following seventeen employees (skilled workers) inspite of their continuous service for the last 7 to 8 years ? If not to what relief are those employees entitled to ?

1.	Sri U. Karunakaran	Operators Drilling
2.	Sri P.T. Kochununni	Do.
3.	Sri C.A. Ganesnan	Do.
4.	Sri Govinda Singh Ravoot	Do.
5.	Sri P.N. Basavaraj	Skilled Workers
6.	Sri Subbaiah	Do.
7.	Sri Venkatesh	Do.
8.	Sri Kariappa	Do.
9.	Subbaraj Urs	Do.
10.	Sri Siromani	Do.
11.	Sri Armugam,	Do.
12.	Sri B.K. Subbaiah	Do.
13.	Sri T.M. Thomas	Do.
14.	Sri P. Rajan Nair	Do.
15.	Sri T.G. Bhaskoran Achar	Do.
16.	Sri P.G. George	Skilled worker
17.	Sri Munirathanam Maidu	Do.

The Second Party has conceded the demand of the First Party as referred to above, which is before this Hon'ble Tribunal for adjudication and issued a Memo in No. PL(SER)/2907 dated 26-9-1975. A copy of it is herewith enclosed. According to said Memo Approval is accorded to confirm the 17 employees referred to in the reference stated above after completion of their one year service with effect from the date noted against each and to pay them arrears of increments as per rules :

Sl. No.	Name : Sriyuths	T. No.	Grade	Date of confirmation
1.	U. Karunakaran	1553	I	1-7-67
2.	P.T. Kochununni	1554	I	1-7-67
3.	C.A. Ganeshan	1555	II	1-7-68
4.	Govindasingh Rawat	1556	II	1-7-68
5.	P.N. Basavaraj	1551	IV	1-8-68
6.	Armugam	1568	IV	1-7-68
7.	T. G. Bhaskarachary	1573	IV	1-7-68
8.	B.K. Subbaiah	1569	IV	1-7-68
9.	S. Subbaiah	1563	IV	1-7-68
10.	K.V. Venkatesh	1565	IV	1-7-68
11.	Subbaraj Urs.	1564	IV	1-7-68
12.	Siromani	1567	IV	1-7-68
13.	Kariyappa	1566	IV	1-7-68
14.	P.G. George	1571	IV	1-7-68
15.	P. Rajan Nair	1570	IV	1-7-68
16.	T.M. Thomas	1572	IV	1-7-68
17.	Munirathanam Naidu	1574	IV	1-7-68

In view of the issue of the above said Memo, the demand of the First Party referred to above is conceded by the II Party.

Both the II Party and I Party referred to above pray this Hon'ble Tribunal to pass an award as stated above in terms of this compromise petition.

Sd/-
M. SELVARAJAN,
First Party

Bhadravathi: the 27th September, 1975.

Sd/-
Second Party

"True Copy"

G.S. Bhagwat, Presiding Officer

[No. L 29011/15/74. LR IV D. III B]

S.H.S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

का० आ० 4845.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इन्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक

अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री धर्मसिंह, तरसेम लाल और रेशम सिंह को उक्त बैंक के जालन्धर उप-कार्यालयों में अंश-कालिक संदेशवाहकों के रूप में पदाभिहित करने की कार्रवाई उचित और न्यायोचित है ? यदि नहीं तो, उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-12011/16/75/डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4845.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Management of the State Bank of India New Delhi, in designating Sarva Shri Dharam Singh. Tarsen Lal and Resham Singh as part-time messengers at the Jullundur Sub-offices of the said Bank is proper and justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

[No. L. 12011/16/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1975

का० आ० 4846.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक, जालन्धर सिटी शाखा के प्रबंधतंत्र की श्री सुच्चा राम को 5 रु० प्रतिदिन की दर से दैनिक दर कर्मकार के रूप में 19 दिसम्बर, 1972 से नियोजित करने और 24 जुलाई, 1974 से उसकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/89/75-डी-II/ए]

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1975

S.O. 4846.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudcation to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Jullundur City Branch, in employing Shri Suchha Ram as daily rated worker at Rs. 5/- per day with effect from the 19th December, 1972 and in terminating his services with effect from the 24th July, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/89/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 4847.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में यूनियन बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र का अपनी गोवर्धन शाखा के रोकड़िया एवं लिपिक श्री डी० सी० शर्मा को 26 अगस्त, 1971 से निलम्बित करना और 6 दिसम्बर, 1974 से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/93/75-डी-II/ए]

ORDER

S.O. 4847.—Whereas the Central Government is of opinion that the industrial dispute exists between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Union Bank of India is justified in suspending Shri D. C. Sharma, Cashier-cum-clerk of the Goverdhan Branch of the said Bank with effect from the 26th August, 1971 and in dismissing him with effect from the 6th December, 1974 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/93/75-DIIA]

आदेश

का० आ० 4848.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्मान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अत: , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० (1) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ोदा के भद्रन शाखा के प्रबन्धतंत्र का, श्री के० आर० मेहता का 19 दिसम्बर, 1974 से सेवाएं समाप्त करना न्योचित है ? यदि नही तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

(सं० एल -12012/96/75-डी० II/ए)

ORDER

S.O. 4848.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda, Bhadran Branch, in terminating the services of Shri K. R. Mehta with effect from the 19th December, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/96/75/DII/A]

आदेश

का०आ० 4849.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इलाहबाद बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री दीप चन्द कपूर का, इलाहाबाद बैंक का बूरा बाजार शाखा में मुख्य रोकड़िया के रूप में नियुक्ति का दावा न्योयोचित है ? यदि हां तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/97/75-डी०II/ए]
आर कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4849.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the claim of Shri Deep Chand Kapoor for posting as Head Cashier at the Burrabazar Branch of the Allahabad Bank is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled.

[No. L. 12012/97/75/DII/A]

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 4850.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th October, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A.,B.L.,

PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 7th day of October, 1975

Industrial Dispute No. 63 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Bank of Madurai Limited, Madurai).

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary, Bank of Madurai Employees' Union, 135, Masi Street, Madras.

AND

The Chairman, Bank of Madurai Limited, Central Office, 378, North Masi Street, Madurai.

Reference :

Order No. L-12011/11/75-D. IIA, dated 29-8-1975 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference, and all other material papers on record and the parties being absent, this Tribunal made the following ex parte.

AWARD

The Government of India, by their order No. L. 12011/11/75-D. II A, dated 29th August, 1975 referred to me for adjudication, a dispute between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited and their workmen in respect of the matters specified below :—

"Whether the action of the management of the Bank of Madurai Limited on transferring the following clerks, who are the office bearers of the Bank of Madurai Employees' Union, as detailed below, is an act of victimisation ? If so, to what relief are these workmen entitled :—

(a) Shri K. Ramalingam, General Secretary from Madurai Tallakulam to Valparai Branch of the said Bank;

(b) Shri R. Rajagopal, Vice President, from Madurai Pownagaram to Salem—Sehvapet Branch of the said Bank;

(c) Shri S. Ramanathan, Treasurer, from Central Office, Madurai to Erode Branch of the said Bank."

2. Parties were served with summons for enquiry on 7-10-1975.

3. The Union did not file claim statements.

4. Today the dispute was called at 11.00 A.M. Neither the workmen nor their union was present. As the workmen were absent, the dispute was passed over till 1-45 P.M. Again when the dispute was called, the Union was absent and no representation was made. It is for the workmen to make out their claims and get on with the dispute. Perhaps the workmen have no interest in the dispute.

5. An award is passed negativing the claims of the workmen and they are not entitled to any relief.

Dated, the 7th day of October, 1975.

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer

ps/

[No. L-12011/11/75/DII/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का० आ० 4857.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी के निचितपुर सेक्शन, डाकघर बांसजोरा जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री पवित्र कुमार बक्शी, उपस्थिति लिपिक और अशोक कुमार मजुमदार, मुन्शी की 11 मई, 1973 से सेवाएं रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[सं० एल-20012/67/75-डी-III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 4851.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nichitpur Section of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad, in stopping the services of Sarva Shri Pabitra Kumar Bakshi, Attendance Clerk and Ashok Kumar Mazumdar, Munshi with effect from the 11th May, 1973, is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-20012/67/75/D. III. A]

New Delhi, the 25th October, 1975

S.O. 4852.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Jaipur Udyog Limited, Phalodi Quarry and their workmen which was received by the Central Government on the 21st October, 1975.

(AWARD)

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. I.T. 14 of 1973

Cement Mine Karmchari Sangh, Sawai Madhopur. ... Applicant.

Vs.

Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur ... Opposite Party.

APPEARANCES:

For the Union- Shri P. K. Sharma.

For the Opposite Party—Shri D. N. Sharma.

Dated of Award—18-8-1975.

AWARD

The Central Government have made the following reference for adjudication to this Tribunal :—

DISPUTE

"Whether the demand of the workmen of Phalodi Quarry for redesignation and regradation of the following 39 beldars, having regard to the duties performed by them, is justified ? If so, to what relief are these workmen entitled and from what date/dates ?

Sl. No.	Name of the workman.	Designation.
1.	Shri Madan s/o. Kalyan	Beldar
2.	Shri Hajari s/o Narayan	"
3.	Shri Onkar s/o Kaniram	"
4.	Shri Kamman s/o Usab	"
5.	Shri Abdul s/o Isab	"
6.	Shri Kalyan s/o Gopal	"
7.	Shri Ramnath s/o Dunilal	"
8.	Shri Gangaram s/o Deviram	"
9.	Shri Bazir Ali s/o Nazir Ali	"
10.	Shri Bhanwar s/o Narayan	"
11.	Shri Hazari s/o Hatutia	"
12.	Shri Pratap s/o Gopal	"
13.	Shri Mitto s/o Girvar Singh	"
14.	Shri Kalu s/o Kushal	"
15.	Shri Kesara s/o Harji	"
16.	Shri Hazari s/o Gangaram	"
17.	Shri Jagannath s/o Bhanwarlal	"
18.	Shri Bajranglal s/o Kunjya	"
19.	Shri Shankar s/o Ram Nath	"
20.	Shri Ramlal s/o Kajor	"
21.	Shri Badri s/o Govinda	"
22.	Shri Ramnarain s/o Bhura	"
23.	Shri Moti s/o Deviram	"
24.	Shri Sheoji s/o Ramnath	"
25.	Shri Prahlad s/o Ramdayal	"
26.	Shri Kishore s/o Jaggan	"
27.	Shri Berda s/o Ramchander	"
28.	Shri Ramkalyan s/o Gangaram	"
29.	Shri Raghunathsingh s/o Bhanwarsingh	"
30.	Shri Suva s/o Bhewaram	"
31.	Shri Heera s/o Mulya	"
32.	Shri Ramniwas s/o Bhura	"
33.	Shri Kalyan s/o Govind	"
34.	Shri Ramniwas s/o Kanu	"
35.	Shri Kana s/o Ramnath	"
36.	Shri Baburam s/o Nathuram	"
37.	Shri Bhura s/o Meru	"
38.	Shri Jagan s/o Ramchander	"
39.	Shri Devilal s/o Mangilal	"

The statement of claim was filed on behalf of the Cement Mines Karmachari Sangh Sawai Madhopur. A reply was also filed on behalf of the management of the Jaipur Udyog Ltd. Phalodi Querry. The sangh was directed to produce evidence in support of their claim but inspite of several adjournments granted to them the Sangh failed to produce any evidence. Since no evidence was produced the claim put up by the Sangh remains/unproved. In the absence of any proof of the claim raised, the Sangh is not entitled to any relief from the Tribunal. The reference is therefore rejected and an award passed accordingly.

UPDESH NARAIN MATHUR, Presiding Officer

[No. L. 29011/59/72/LRIV/DIIIB]

New Delhi, the 6th October, 1975

S.O. 4853.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Tungsten Mining Project, Government of Rajasthan, Degana and their workmen which was received by the Central Government on the 22nd October, 1975.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL JAIPUR

Case No. I.T. 34 of 1972

Tungsten Mine Workers Union, Degana .. Applicant.

Vs.

Tungsten Mine Project Degana. .. Opposite Party.

APPEARANCES:

For the Union—Shri Bharat Bhushan Arya.

For the Management (Project)—Shri J. P. Gupta.

Date of Award—22-8-1975.

AWARD

The Central Government have made the following reference for adjudication to this Tribunal :—

DISPUTE

"Whether the action of the management of Tungsten Mining Project is justified in terminating the services of Shri Mool Singh Mate, with effect from the 10th August, 1970. If not to what relief is he entitled ?".

The statement of claim was filed on behalf of the Tungsten Mine Workers Union. The demand made on behalf of the union is that Mool Singh was a certified Mate in the Tungsten Project. He was suffering from Naharu (Bala) बाला and as the pain increased on 11-8-70 he went on leave under intimation to the management and sent his leave application in writing, but the management did not accept the application and terminated his services vide order No. L.N. Tong/Project/F. 38(37)/70-71/645 dated 5-9-1970. It is alleged that no notice fo termination was given to him. The management terminated his services to victimize him because of his trade union activities. It is therefore prayed that Mool Singh be reinstated with back wages.

A reply on behalf of the management was filed in which it is pleaded that Mool Singh was working as Gang Mate only and not as a certified mate. He worked upto 8-8-1970. On 10-8-1970 he came to the office but was refused to work

as ordered to him and left the project premises. He has submitted a letter in the office on 10-8-1970 for which a receipt was given to him. It is denied that he sent any application to the Management which was not accepted. The management terminated his services as per rule 11(A) of the Standing Orders being absent without leave upto 19-8-1970.

Evidence on behalf of both the parties was recorded.

I have perused the evidence on record and heard the arguments advanced on behalf of the parties. In my opinion the union have failed to established that Mool Singh had sent an application through his son Narpat Singh which was not accepted by the management. A perusal of the statement of Narpat Singh would show that he could not stand the cross examination of the other party. He had contradicted the facts which he deposed in the affidavit in the cross examination. He was the only witness which could say whether he did go to the management's office to deliver the leave application. The other evidence produced also does not support the facts alleged by Mool Singh. The witnesses on behalf of the management Shri Sitaram who was Mines Manager in the Tungsten Project at that time and was fully aware with the facts of the case, has stated that no application on behalf of Mool Singh was ever received in the office. In view of this insufficient evidence of the fact I am not prepared to accept the contention that Mool Singh remained on leave during the disputed period. He remained absent without leave.

The point now raised is whether in view of the finding that Mool Singh remained absent without leave, the services of Mool Singh could be terminated under rule 11(A) of the Standing Orders. A perusal of rule 11(A) would show that the case of Mool Singh is not covered under it. It deals with a case where a workman remains absent beyond the period of leave granted or subsequently extended. In that case he losses his lien unless he reports within 8 days from expiry of the leave, as provided in sub-clause (A) of Rule 11. In the case before us Mool Singh remained absent without any leave and therefore his case is covered under sub-clause (C) of rule 11 of the Standing Order. His absence without leave has rendered him liable for disciplinery action for misconduct. Since he has committed a misconduct by remaining absent without leave his removal could be affected through the procedure laid down in the Standing Orders, namely that he should be charge sheeted and an enquiry held. Admittedly no charge sheet was served for his absence nor was any enquiry held. Therefore his removal on the ground of misconduct without any enquiry is illegal. The order of removal issued by the management is therefore liable to be set aside.

The management has filed a letter issued by the Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation Ltd. informing that Mool Singh has been appointed as certified mining mate on 21-8-1972 in the pay scale of Rs. 180—425 and has been working with them since then. In this connection it is submitted on behalf of the management that the Tungsten Mining Project has not now been taken over by the Rajasthan State Industries and Mining Corporation and therefore Mool Singh has been employed by the same management and therefore there is no question of reinstatement now. In view of this fact there is no question of ordering reinstatement of Mool Singh who is now employed on a better scale of pay. However he is entitled to full back wages and all other benefits from the date of his removal upto 21-8-1972, when he was re-employed. The reference is answered accordingly.

UPDESH NARAIN MATHUR, Presiding Officer

[No. L. 29012/6/71-LR IV/DIIIB]

S.O. 4854.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Karnataka, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Dalmia Cement (Bharat) Limited, Hospet and their workmen which was received by the Central Government on the 22nd October, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KARNATAKA, BANGALORE

Reference No. 2 of 1973 (Central)

I PARTY :

Sri K. Venkataramanaiah C/o Shri M. Ismail, near Head Post Office, Hospet Post Office, Bellary District.

Vs.

II PARTY :

The Branch Manager, M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Hospet Post Office, Bellary District.

APPEARANCES :

For the I Party : Shri K. Ramdass, Advocate, Bangalore.

For the II Party : Shri B. T. Parthasarathy, Advocate, Bangalore.

ORDER OF REFERENCE

(Government Order No. L-29012/12/73-LR. IV dated 28-5-1973).

AWARD

The Central Government empowered under section 7-A and Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) by their Order No. L-29012/12/73-LRIV dated 28-5-1973 referred the dispute existing between the Dalmia Mine Employees' Union, Hospet, and the Management of Messrs. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Patel Nagar, Hospet, in relation to the dismissal of one of its employees Shri K. Venkataramanaiah, Fitter-cum-Driver, with effect from 27th November, 1972 to the Industrial Tribunal at Bangalore as then constituted for adjudication on the following points of dispute :—

"Whether the action of the management of Messrs. Dalmia Cement (Bharat) Limited, Hospet Post Office, Bellary District, in terminating the services of Shri K. Venkataramanaiah, Fitter-cum-Driver with effect from the 27th November, 1972 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

1. On receipt of the above Reference, the same came to be numbered as Reference No. 2/73 (Central) on the file of this Tribunal and notices were issued to both the parties to file statement of demands.

2. The workman, Shri K. Venkataramanaiah, (hereinafter called as the I Party) filed his claim statement on 2-7-1973. He submitted that he has not abandoned his services and that the management of Messrs. Dalmia Cement (Bharat) Limited, was not justified in taking action under Standing Order 8(b) of the Certified Standing Orders applicable to him. He was told that his name was struck off from the rolls of the company with effect from 27-11-1972. Thereupon he made a representation for reconsideration of the said order, but he had received a reply dated 14-12-1972 that it was not possible to revoke the order. The sick leave dated 11-11-1972 was not properly refused. The endorsement refusing sick leave said that failure to report to duty would result in disciplinary action. By implication, it meant that disciplinary action would be taken under Standing Order 14(VI) read with Standing Orders 15 and 16 of the Standing Orders applicable to him. The application for the sick leave from 11-11-1972 was intended to overlap the leave already granted from 14-11-1972 to 16-11-1972 (both days inclusive). The application for sick leave should be taken

to mean that the leave already granted should be treated as part of sick leave continuously from 11-11-1972 but not independently. The absence is, therefore, from 11-11-1972 and not from 16-11-1972 as contended in the order dated 27-11-1972 terminating his services. He is, therefore, governed by the provisions contained by the Standing Order 14(VI) of the Standing Orders applicable to him, Hence any termination by way or striking off the name from the rolls or otherwise without holding an enquiry as contemplated in Standing orders 15 and 16 of the Certified Standing Orders applicable to him would be illegage and ultra vires the standing orders. In this connection no enquiry was held at all.. He also pleaded victimisation and prayed for an Award reinstating him in his former post of Fitter-cum-Driver with backwages, continuity of service and status quo ante.

3. The Management of Dalmia Cement (Bharat) Limited, (hereinafter called as the II Party) filed a counter statement on 25-8-1973. They contended that there is no positive act of termination of services by the Management of II Party. The I Party was only considered as having abandoned his services and as such, the question of taking any disciplinary action against the concerned workman does not arise at all. The invoking by them of the standing order 8(b) is quite in order and there is no act of termination. The reference of the dispute on the alleged termination of service is untenable either on facts or in law and I Party is not entitled to any relief and hence requested to answer the Reference in negative with costs.

4. The I Party filed the rejoinder to the counter statement filed on 11-10-1973 contended that Clause 8(b) of the Standing Order is not applicable to this case and notice of termination issued to him is not proper and opposed to the principles of natural justice and hence submitted to answer the Reference in his favour with costs.

5. On receipt of a common order No. L. 26012/6/73-LRIVD-IV-B dated 21-7-1975 from the Central Government transfering the above Reference in the name of the present Presiding Officer, Industrial Tribunal, as constituted at Bangalore, the case was called on 23-9-1975 and on that day, an application was received signed by the II Party and verified by Sri T. R. Vohra, Branch Manager, by post along with the Memorandum of Agreement arrived at between the concerned workman Sri A. Venkataramanaiah and the II Party requesting to dismiss the above Reference without costs, the same being settled out of court. Sri K. Ramdas for the I Party who was present in court took adjournment to report about the above settlement after contacting the I Party and hence the case was adjourned to 10-10-1975. On that day, Sri Zaffar Ahmed, Junior of Sri B. T. Parthasarathy for the II Party filed 3 copies of memos of Settlement and requested to pass an award in terms of the Memo of Settlement arrived at between the concerned workman and the employer. Sri K. Ramadass for the I Party absent and there was no one present on behalf of the I Party to make any other submission. I have carefully gone through the Memo of Settlement. By virtue of this settlement, the II Party agreed to pay a sum of Rs. 300/- as ex-gratia payment in full and final settlement of all the claims of the I Party whatsoever with the II Party. In consideration of this, the I Party withdraws all his claims for reinstatement and other benefits made on the II Party sought in his application dated 30-1-1973 addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central) Bellary, which has being pending as Industrial Dispute in the above Reference (Central) on the file of this Tribunal and the I Party-workman has agreed to have his case dismissed as settled out of court without costs. In witness whereof, the parties have set their respective hands to the Memo of Settlement on 3-9-1975. Having got myself satisfied that the terms of settlement are fair, reasonable and genuine one, the same is recorded and accepted.

In view of what has been stated above, the Reference is dismissed, the same being settled out of court. No order as to costs. A copy of Memo of Settlement shall form a part of this Award.

'True Copy'

G. S. Bhagwat

Presiding Officer,

Industrial Tribunal,

Bangalore.

MEMORANDUM OF AGREEMENT

This agreement made on this the 3rd September, 1975 Between K. Venkataramiah, son of K. Kotiah, aged 28 years, residing at Dam Road, Hospet, Bellary District, in Karnataka, hereinafter called the First Party (which expression shall include unless repugnant to the context or meaning thereof, his successors, legal representatives and heirs) of the First Part and M/s. Dalmia Cement (Bharat) Limited, a Company incorporated under the Indian Companies Act, 1913 and having its Registered Office at Dalmiapuram in the State of Tamil Nadu and mining Iron Ore Bharatarayanaharuvu Hill Top of Hospet, Bellary District in Karnataka, hereinafter called the "Company" "Second Party" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof shall include its successors and assigns) of the Second Part.

Whereas, the First Party was employed by the Second Party as Fitter-cum-Driver and his name was struck off by the Second Party as voluntary abandonment of job on 27th November, 1972 in accordance with the Certified Standing Orders of the Company.

And Where, the First Party approached the Assistant Labour Commissioner (Central), Bellary under Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 for re-instatement, which has been referred to the Industrial Tribunal (Central), Bangalore, which is pending for adjudication as Industrial Dispute No. 1 of 1973.

And whereas, pending the said adjudication, the First Party having approached the Second Party for amicable settlement of his case by negotiations, the Parties hereto have settled the issue out of the Court as under.

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Second Party hereby agrees to pay a sum of Rs. 300-00 (Rupees three hundred only) as ex-gratia payment in full and final settlement of all the claims of the First Party whatsoever with the Second Party.

2. In view of this, the First Party hereby withdraws all his claims for re-instatement and other benefits made on the Second Party sought in his application dated 30th January, 1973 addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central), Bellary which has been pending as Industrial Dispute No. 1 of 1973 on the file of Hon'ble Industrial Tribunal (Central), Bangalore and has agreed to have his case dismissed as settled out of Court without costs.

In witness whereof, the Parties hereto have set their respective hands this the 3rd day of September, 1975.

K. Venkataramaiah,
First Party.

Witnesses :—

1. B. Mareppa,
Patelnagar,
Hospet.

2. P. Ganapathi,
Patelnagar,
Hospet.

For Dalmia Cement (Bharat) Limited
J. R. Vohra,
Branch Manager and Duly Constituted Attorney.

True Copy
Zaffar Ahmed
Advocate.

[No. L29021/12/73/LR IV/D-III B]

G. S. BHAGWAT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4855.—यत: केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1414 तारीख 25 अप्रैल, 1975 द्वारा किसी तेल क्षेत्र में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 मई, 1975 से छ: महीने की अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 नवम्बर, 1975 से छ: मास की कालावधि को और अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा० संख्या एस-11017/8/75-डी-1 ए]

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4855.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provision of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1414 dated the 25th April, 1975 service in any oil-field, to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months from the 22nd May, 1975.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd November, 1975.

[F. No. S-11017/8/75/D-IA]

New Delhi, the 31st October, 1975

S.O. 4856.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Goverment on the 25th October, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

Justice E. K. MOIDU ...... Presiding Officer.

Reference No. 12 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Colliery,

AND

Their workmen

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri N. Das, Advocate, with Shri B. N. Lala, Asstt. Chief Personnel Officer, and Shri V. N. Murarka, Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen—Shri N. C. Roy, Advocate.

State : West Bengal Industry : Coal Mine

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-190/2/74-LRII, dated 29th January, 1975, referred the following industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Colliery and their workmen, to this tribunal, for adjudication :

"Whether the management (Coal Mines Authority Limited) in relation to Nag's Kajora Jambad Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan are justified in not providing Sarvashri K. Bale Kuty, T. K. Mohamed and P. K. Modankuty, Coal Cutting Machine Drivers in Category VI? If not to what relief are the workmen entitled?"

2. The workmen concerned in the reference are K. Bale Kuty, T. K. Mohamed and P. K. Modankuty. Their case was sponsored by the General Secretary, Khan Shramik Congress, P. O. Ukhra, District Burdwan. The case of the union was that these three workmen were wrongly placed in Category No. V instead of putting them in Category No. VI, on the basis of the Wage Board recommendation for the Coal Mining Industry. According to them, they had been placed in Category No. VIII while they worked in the coal mine which was then under the management of Nag's Kajora Jambad Colliery but they were wrongly placed in Category No. V with effect from 15-8-67. When the Coal Mines Authority came into power on the basis of the nationalisation of the coal mines they made representation to place them in correct category and pay their additional emoluments but they refused to do so. Hence they moved the Assistant Labour Commissioner for conciliation on 23-10-73 but no conciliation could be effected as the management did not co-operate. Therefore, the reference was made to this tribunal for

adjudication, The Union wanted this tribunal to pass an award holding that the refusal of the employers to put the workmen in Category No. VI with effect from 15-8-67 was illegal with a directon to place the workmen in Category No. VI with effect from 15-8-67 on payment of arrears of wages.

3. The management raised the objection that the reference itself had become infunctions because there is no subsisting industrial dispute in as much as the union which espoused the cause of the workmen had retired from the contest and that, therefore, the tribunal has no jurisdiction to try the reference as if there is a subsisting industrial dispute. It was also contended that the union which had supported the cause of the workmen did not represent the employees of the Coal Mines Authority in the particular colliery and as such the union had also no subsisting right to represent the workmen. On merits it was alleged that the workmen had no right to be included in Category VI, as it required the possession of Gas testing certificate, which the workmen did not obtain so far. The workmen having failed to obtain such a certificate they are not entitled to be included in Category VI and therefore the reference has no merit.

4. The first question that arises for determination as a preliminary issue in whether there has been any subsisting industrial dispute between the employers and the workmen in this case.

5. The reference was made by the Government under its Order dated 29th January, 1975. Prior to the reference there was an attempt at conciliation before the Assistant Labour Commissioner, Central, on the basis of the letter dated 23rd October, 1973 which was sent by the Khan Shramik Congress on behalf of the three workmen. The employer, however, did not attend the conciliation proceeding. So, an ex-parte order was made by the Conciliation Officer for a reference under the Industrial Disputes Act, 1947. It was accordingly that the reference was made.

6. On 4-2-1975 the reference was registered before this tribunal. Summons were issued on both the employer and the General Secretary, Khan Shramik Congress. The Khan Shramik Congress received the summons on 26-2-1975 but they did not come forward to participate in the proceeding. On the other hand, the workmen filed a joint statement dated 6-3-1975 to the effect that they shall be permitted directly to appear before the Tribunal in respect of the dispute in question and that they did not want the support of the union. Thereafter on 29-8-75 the workmen authorised one Sri N. C. Roy, Advocate to appear on their behalf and take part in the proceeding. It was accordingly that the preliminary point has come up for determination before the Tribunal.

7. It is admitted that the Khan Shramik Congress or its *office-bearers do not lend support to the dispute in question.* The workmen themselves want to intervene and take part in the proceeding. They have disputed one learned Advocate to represent their case before the tribunal. It was clear that when the reference was made there was an industrial dispute between the employer and the employees for determination by this tribunal. But the Khan Shramik Congress has retired from the proceeding after the reference was registered before this tribunal. The union is no more a party to the proceeding. The question is whether the workmen can independently participate in the proceeding as individual workmen on the basis of an alleged subsisting industrial dispute.

8. In this regard I may refer to few decisions which will throw some light on the controversy in issue. It is under Sec. 36 of the Industrial Disputes Act, 1947 that the question as to the representation of parties has to be determined. Sec. 36 is closely connected with Sec. 2(k) of the Act which defines "industrial dispute". At no stage it can be said that the concerned workmen is a party to the Industrial dispute independently of the union. In the case of Ram Prasad Vishwakarma and Industrial Tribunal, Patna and others, 1961 I LLJ, 504, the Supreme Court had to consider the question whether a workman could ask for a representation of a person of his own choice after his case had been represented and was being sponsored by the trade union of which he was a member, on the ground that he had lost faith in the office bearer of the union who was adjudicating his case. From the principle that a dispute between an individual workman and his employer could not be an industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) unless it was taken up by a Union of workmen or by a considerable number of his co-workers, the Court deducted the corollary that an individual workman is at no stage a party to the industrial dispute independently of the Union. The union or those workmen, who by their sponsoring had turned the individual dispute into an industrial dispute, could, therefore, claim to have a say in the conduct of the proceedings before the tribunal. Though the Court recognised the position that the provisions in Sec. 36(1) entitles a workman who is a party to the dispute to be represented by an officer of a Trade Union of which he is a member, it did not think it wise to lay down a general proposition of law in the matter and contended itself by saying that the ordinary rule should be that such representation of an officer of the trade union should continue throughout the proceeding in the absence of exceptional circumstances which may justify the Tribunal to permit other representative of the workman concerned. In an industrial dispute of a collective nature, for instance, the disputes pertaining to employment or non-employment or terms of employment, or with condition of labour of workmen as a class, the pronouncement made by the Supreme Court in the case referred to above still holds the field as in such a case an individual workman is at no stage a party to the industrial dispute independently of the union or workers as a class where there is no union. This decision has been followed by the Patna High Court in the case of Dr. Chandra Kala and Sone Valley Portland Cement Company, Ltd., Japla, and another, 1962 II LLJ, 395. The following remarks in the above decision may be noted :

> "It is manifest from the records that the dispute was taken up by the union in its representative capacity and not by the then secretary in his personal capacity and hence it assumed the character of industrial dispute. In such situation it is manifest that the concerned individual workman cannot be in her own right a party to the industrial dispute which has been referred to the labour court. The legal position is that when an individual workman is a party to an industrial dispute he is a party not independently of the union which has espoused his cause, and the main parties to the industrial dispute before the labour court are therefore the employer and the union which has taken up the cause of the individual workman. In these circumstances the ordinary rule is that the individual workman should be represented before the labour court through the officer of the trade union which has taken up his cause."

In the case of Central Provinces Transport Services, Ltd., and Raghunath Gopal Patwardhan, *1957 I L.L.J., 27,* Venkatarama Ayyar, J., stated as follows at page 30 :

> "Notwithstanding that the language of S. 2(k) is wide enough to cover a dispute between an employer and a single employee, the scheme of the Industrial Disputes Act does appear to contemplate that the machinery provided therein should be set in motion, to settle only disputes which involve the rights of workmen as a class and that a dispute touching the individual rights of a workman was not intended to be the subject-matter of an adjudication under the Act when the same had *not* been taken up by the union or a number of workmen."

The whole point is as to whether the employer is fighting a dispute with a large number of workmen. Until that test is passed, an individual dispute cannot be transformed into an industrial dispute. In the instant case admittedly there is a very large number of other workmen in the coal mine in question. There is no evidence that those workmen had at any time supported the workmen in the instant case in respect of the dispute under consideration. The union having withdrawn from the controversy the dispute *in question* ceased to be an industrial dispute. The above view has also been confirmed in a decision reported in Express Newspaper Private Ltd., vs. First Labour Court, West Bengal and others, 1959 I LLJ, 600. The relevant portion

of the judgment in that decision has been quoted with authority in a later decision of the Patna High Court reported in Jharia Fire-Bricks and Pottery Works and Labour Court, Chotanagpur Division and others, 1967 1 L.L.J., 607. The portion of the judgment referred to above reads as follows:

> "If a large number of workmen of a particular industry become members of a union which is not, strictly speaking, the union of the industry or the establishment concerned, the principle might be extended. The whole point is as to whether the employer is fighting a dispute with a large number of his workmen . . ."

It is apparent from a consideration of the law on the point as well as the facts of the instant case that the three workmen have no legs to stand upon in respect of the dispute in question in view of the fact that the union has withdrawn from the contest. The industrial dispute which was in existence ceased to be one because the cause of the workman is no longer found to be espoused by the union. The workmen have no independent right to sustain a claim against the employer when their case is not being espoused by a union of which they are members or a large number of workmen of the same establishment in respect of the matters. Probably the union which originally espoused the cause of the workmen retired from the proceeding as they felt the proper remedy of the workmen was not through a reference to this tribunal. They would have found out some other remedy which would be beneficial to the entire body of the workmen as a class.

9. Having found that there is no industrial dispute in existence the only conclusion possible is that the reference is not sustainable and it is, therefore, rejected.

In the result, the reference is rejected.

The 18th October, 1975.

E. K. MOIDU,
Presiding Officer

[No. L19012(2)/74-LRII/D. III B]

S.O. 4857.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Star Construction and Transport Company, contractors and Messrs. India Cements Limited, Sankari and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th October, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,

PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,

MADRAS

Industrial Dispute No. 47 of 1975.

Tuesday, the 7th day of October, 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of M/s. Star Construction and Transport Company, Sankari.)

The workmen represented by: The Secretary, India Cements and Mining Workers Union, Sankari West, Post Office, Salem District.

AND

1. The General Manager, Messrs. Star Construction and Transport Company, Sankari West, Post Office, Sankari Salem District.

2. The General Manager, India Cement Limited, Sankari West, Salem District.

Reference:

Order No. L-29011/39/74/LR. IV-D.O. IIIB, dated 9-7-1975 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference, and all other material papers on record and the parties being absent, this Tribunal made the following:

AWARD

The Government of India, in their order No. L 29011/39/74/L.R.IV D.OIII B, dated 9-7-1975, referred a dispute between the employers in relation to M/s. Star Construction and Transport Company, Sankari, Contractors and M/s. India Cements Ltd., Sankari and their workmen in limestone mines in respect of the matters specified below:—

> Whether the following demands of the workmen of Messrs. Star Construction and Transport Company, Sankari, Contractors and Messrs. India Cements Limited, Sankari, and employees in limestone mines are justified? If so, to what relief are they entitled?

Demands

(1) Provision of housing accommodation to workmen.
(2) Provision of a Weigh Bridge at quarries.
(3) Permanency of canteen workers.
(4) Payment of dust allowance to workmen.

2. Parties were served with summons, but they were absent right through. On 22-8-1974, a letter dated 19-8-1975 was received from the Union stating that all the matters were settled by direct talks and hence proceedings may be dropped.

3. As the parties were absent, fresh summons were ordered to be issued for their appearance on 7-10-1975. They were absent also on 7-10-1975.

4. In the circumstances, I feel no purpose would be served by keeping the reference pending further. I think that the dispute might have been settled between parties and so the workmen are not interested in the dispute.

5. I pass an award negativing the claims of the workmen and they are not entitled to any relief.

Dated, this 7th day of October, 1975.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal

[No. L-29011/39/74/LRIV/DIIIB]

S.O. 4858.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramakrishna Magnesite Mines, Salem and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th October, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B. A., B. L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 38 of 1974

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Balakrishna Magnesite Mines, Salem.

The workmen represented by :

The General Secretary, Salem District Magnesite Labour Union, Suramangalam, Salem-5.

And

Shri K. G. Muniswamy Chetty, Owner, M/s. Ramakrishna Magnesite Mine, No. C-34, Fairlande, Salem-4.

Reference :

Order No. L-29011/45/74-LRIV, dated 23-10-1974 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru A. Pariathambi, General Secretary of the Union persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and the management being absent and this Tribunal made the following:

AWARD

By order No. L-290011/45/74-LR. IV, dated 23-10-1974, the Government of India, Ministry of Labour, the following dispute between the employees and the Management of Ramakrishna Magnesite Mines, Salem have been referred for adjudication by this Tribunal.

"(1) Whether the demand for increased wages by workmen of the Mine is justified ? If so, what should be the wage structure and from what date ?

(2) Whether the action of the management in terminating the services of the 17 workmen (mentioned below) is justified ? If not, to what relief they are entitled ?

1. Kundan S/o Sadayappagounder.
2. Ravi S/o Anaigoundan.
3. Jayaraman S/o Kaliappan.
4. Chinnapaiyan S/o Ramaswamy.
5. Venkatachalam S/o Chinnappan.
6. Manickan S/o Ramaswamy.
7. Chellamal W/o Palani.
8. Chimmammal W/o Maniokam.
9. Pappa W/o Lakshmanam.
10. Unnamalai W/o Subramani.
11. Periammal W/o Beragounder.
12. Palaniammal W/o Kamaleman.
13. Dhanam W/o Chinnapaiyan.
14. Kayeriammal W/o Raja Gounder.
15. Pappathi W/o Sivalinga.
16. Madhammal W/o Loganathan.
17. Kuppammal W/o Chinnathambi.

2. The Secretary of the Salem District Magnesite Labour Union has filed a claim statement alleging that the wages paid to the workmen of the respondent concern is very low, that in all other similar establishments at Salem, higher rates of wages are paid and that the workmen are unable to maintain the minimum standard of life with the present wage paid by the respondent-company. The other allegation is that on 30-6-1974 the management all of a sudden terminated the services of 17 employees mentioned in the order of reference. The Union prays for an award for enhanced pay and for reinstatement.

3. The respondent management though served was absent and hence set ex-parte.

4. Issue No. 1 : On behalf of the workmen, the Secretary of the Salem District Magnesite Labour Union argued that the present wages and Dearness Allowance paid to the workers are very low and in all other similar establishments, higher rates are paid. He filed Exs. W-1 to W-3 to show that higher rates of wages and Dearness Allowance are paid in similar establishments at Salem. There is no evidence contra on the side of the management as to why no reliance should be placed on Exs. W-1 to W-3. The Union has made out a prima facie case for the enhanced wages and Dearness Allowance claimed in the plain statement. I find this issue in favour of the Union.

5. Issue No. 2: The grievance of the Union is that the 17 workmen were dismissed from services because they demanded higher wages. There is no evidence contra. Under those circumstances, the contentions of the union are accepted. This issue is found in favour of the Union.

6. An award is passed allowing the claims of the union regarding the wages demanded and also the prayer for reinstatement of 17 workmen. The management is directed to pay the costs of the Union.

Dated, this 10th day of October, 1975 at Salem.

T. Palaniappan,
Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For both sides : Nil.

DOCUMENTS MARKED

For workmen :

Ex. W-1/22-3-74—Memorandum of settlement under section 18(1) of the I. D. Act, 1947 between the Management of M/s. Burn and Co., Ltd., Salem and their workmen.

Ex. W-2/19-3-74—Memorandum of settlement under sectiton 18(1) of the I. D. Act, 1947 between M/s. Salem Magnesite Private Ltd., Salem and their workmen.

Ex. W-3/20-3-1974—Memorandum of settlement under section 18(1) of the I. D. Act, 1947 between the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal

Note : Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

[L 29011/45/74/LRIV/DIIIB]

का०आ० 4859:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1721 तारीख 21 मई, 1975 द्वारा कोयला उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 21 मई, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 21 नवम्बर, 1975 से छः मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/1/75/डी-आई/ए)]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

S.O. 4859.—Whereas the Central Government being satisfied that public interest so required, had declared by a notificatiton made in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1721 dated the 21st May, 1975, the coal industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 21st May, 1975;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 21st November, 1975.

[No. S. 11017/1/75/DI/A]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4860.—भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या 351 (अ), तारीख 11 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "भारत रक्षा नियम" शब्दों के लिये "भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० एस-42025/21/74-डी०के० आई ए]

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1975

S.O. 4860.—In exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 the Central Government hereby make the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. 351(E) dated the 11th July, 1975, namely :—

In the said order for the words "Defence of India Rules", the words "Defence and Internal Security of India Rules" shall be substituted.

[No. S-42025/21/74-DKIA]

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4861.—भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश सं० 308 (अ), तारीख 3 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश "भारत रक्षा नियम" शब्दों के लिये "भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[सं० एस 42025/13/75-डी० आई० ए]

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 4861.—In exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. 308(E) dated the 3rd July, 1975, namely :—

In the said order for the words "Defence of India Rules", the words "Defence and Internal Security of India Rules" shall be substituted.

[No. S-42025/13/75-DIA]

आदेश

का० आ० 4862.—भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या 350 (अ) तारीख, 11 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "भारत रक्षा नियम" शब्दों के लिये "भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० एस-42025/14/75-डी०के० आई० ए]

ORDER

S.O. 4862.—In exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. 350(E) dated the 11th July, 1975, namely :—

In the said order for the words "Defence of India Rules", the words "Defence and Internal Security of India Rules" shall be substituted.

[No. S-42025/14/75-DKIA]

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4863.—मसर्स बंशीधर परमसुखदास आयल मिल्स आगरा, यू०पी० को, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 27 मई, 1961 में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1195 तारीख 19 मई, 1961 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952

(1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के सभी उपबन्धों से छूट दी गई थी,

और उक्त स्थापन का नाम और पता "बंसीधर परमसुखदास आयल मिल्स, आगरा, यू०पी०" से बदल कर "बी०पी० आयल मिल्स लिमिटेड, मैथान, आगरा, यू०पी०" रख दिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करता है कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 के क्रमसंख्या 18 के सामने आने वाले "बंसीधर परमसुखदास आयल मिल्स आगरा, यू० पी०" पद के स्थान पर "बी० पी० आयल मिल्स लिमिटेड, मैथान, आगरा, यू० पी०" पद रखा जाए।

[सं० 9(4)/61-पी० एफ० (ii)]

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 4863.—Whereas Messrs Bansidhar Premsukhdas Oil Mills, Agra, U.P. was granted exemption from the operation of all the provisions of the Employees Provident Funds Scheme under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1195 dated the 19th May, 1961 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 27th May, 1961;

And whereas the name and address of the said establishment has been changed from "Bansidhar Premsukhdas Oil Mills, Agra, U.P." to "B. P. Oil Mills Limited, Maithan, Agra, U.P.";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby directs that for the expression "Bansidhar Premsukhdas Oil Mills, Agra, U.P." occurring against serial No. 19 of Schedule I to the said *notification*, the expression "B. P. Oil Mills Limited, Maithan, Agra, U.P." shall be substituted.

[No. 9(4)/61-P.F.-II]

का० आ० 4864.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्व श्री एस० बी० दवे, के० पी० औसेफ, पी० बी० भट्ट और आई० बी० पारिख को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए-12016(3)/74-पी०एफ० i]

एस० एस० सहस्रानमन, अवर सचिव

S.O. 4864.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri S. B. Dave, K. P. Ouseph, P. B. Bhat and I. B. Parik to be Inspectors for the whole of the State of Maharashtra for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield of a controlled industry or in relation to any establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/3/74-PF. I]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4865.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरविंद फैब्रिक्स, सी-36, उद्योग नगर, नवसारी जिला बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस 35019(129)/75-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 8th October, 1975

S.O. 4865.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arvind Fabrics, C-36, Udyognagar, Navsari, District Bulsar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This *notification* shall be deemed to have come into force on the twentyeighth day of February, 1975.

[No. S-35019(129)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4866.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रो एसियाटिक (प्राइवेट) लिमिटेड, 1 सुदर्शनपुर, औद्योगिक क्षेत्र, जैपुर-6, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की मई के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस 35019(49)75-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 4866.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to thee establishment known as Messrs Electro Asiatic

(Private) Limited, 1, Sudarshanpur, Industrial Area, Jaipur-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1974.

[No. S-35019(49)/75-PF. II]

का०ग्रा० 4867.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी पटेल ग्रायरन एण्ड ब्रास फैक्ट्री, स्टेशन रोड, पेटलाड, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर कुटुम्ब पेंशन निधि ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

ग्रतः, ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह ग्रधिसूचना 1973 की ग्रप्रैल, के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(122)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4867.—Whereeas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Patel Iron and Brass Factory, Station Road, Petlad, District Kaira have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of sction 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1973.

[No. S. 35019(122)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 17 ग्रक्तूबर, 1975

का०ग्रा० 4868.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ई० के० हाजी मोहम्मद मीर साहिब एण्ड सन्स, 10, बेपेरी हाई रोड, मद्रास-2 नामक स्थापन से सम्बन्द्व नियोजक ग्रौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर कुटुम्ब पेंशन निधि ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू किये जाने चाहिये;

ग्रतः, ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह ग्रधिसूचना 1973 के ग्रक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(167)/73-पी०एफ० II(i)]

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 4868.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of employees in relation to the establishment known as Messrs E. K. Hajee Mohamad Meera Sahib and Sons, 10 Vepery High Road, Madras-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Ast, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1973.

[No. S. 35019(167)/73-PF. II(i)]

का०ग्रा० 4869.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि ग्रौर कुटुम्ब पेंशन निधि ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय में ग्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 ग्रक्तूबर, 1973 से मैसर्स ई०के० हाजी मोहम्मद मीर साहिब एन्ड सन्स, 10, बेपेरी हाई रोड, मद्रास-3 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(167)/73-पी०एफ० II(ii)]
ग्रार०पी०नरूला ग्रवर सचिव

S.O. 4869.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of October, 1973, the establishment known as Messrs E. K. Hajee Mohamad Meera Sahib and sons, 10 Vepery High Road, Madras-3, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(167)/73-PF. II(ii)]
R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 ग्रक्तूबर, 1975

का०ग्रा० 4870.—कर्मचारी राज्य बीमा ग्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रौर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रधिसूचना संख्या का० ग्रा० 56 तारीख 26 दिसम्बर, 1974 के ग्रनुक्रम में केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के केन्द्रीय भण्डार ग्रौर पूर्ति प्रभाग, दिल्ली को उक्त ग्रधिनियम के प्रवर्तन से, 1 जून, 1975 से 31 मई, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की ग्रौर ग्रवधि के लिए छूट देती है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के ग्रधीन है, ग्रर्थात्:--

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जहां कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम ग्रौर पदाभिधान दिखाए जाएंगे।

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनके कि वे इस ग्रधिसूचना में दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त ग्रभिदायों के ग्राधार पर हकदार हो गए हों।

(3) छूट प्राप्त ग्रवधि के लिए, यदि कोई ग्रभिदाय किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे।

(4) उक्त कारखाने, का नियोजक उस अवधि के बावत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के वर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम साधारण विनियम 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी।

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बावत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत कर्मचारी राज्य बीमा (असाधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथोपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के हकदार हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा, अर्थात् :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं।

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या पदधारी के समक्ष ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें वैसी जानकारी दें ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक, उसके अभिकर्ता या सेवक या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने को छूट प्रदान करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां, जिनमें कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस 38014/11/74 एच आई]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 4870.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 56 dated the 26th December, 1974, the Central Government hehreby exempts regular employees of the Central Stores and Supply Division, Delhi belonging to the National Seeds Corporation Limited, New Delhi from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st June, 1975, upto and inclusive of the 31st May, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of sectiton 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—

(a) required the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Directorate General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/11/74-HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 1975

का०आ० 4871.—केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 531 तारीख 2 मार्च, 1961 द्वारा श्री पूरणचन्द्र दयालदास चौधरी तथा बख्तावर सिह् नाग को खानों के निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

तथा उक्त श्री पूरणचन्द्र दयालदास चौधरी तथा श्री बख्तावर सिह् नाग ने क्रमश; इक्कतीस मई 1975 अपराह्न से 28 अप्रैल 1975 के पूर्वाह्न से सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 96 और 102 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।"

[सं० क-39012/2/74- एम०आई०]

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 4871.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government had appointed Shri Puranchandra Dayaldas Chaudhary and Shri Bakhtawar Singh Nag, as Inspectors of Mines by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment number S.O. 531, dated the 2nd March, 1961 ;

And whereas the said Shri Puranchandra Dayaldas Chaudhary and Shri Bakhtwar Singh Nag have resigned from service with effect from the afternoon of the 31st May, 1975, and the forenoon of the 28th Aprol, 1975, respectively;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely :—

In the said notification, serial Nos. 96 and 102 and the entries relating thereto shall be omitted.

[File No. A-39012/2/75-M.I]

का० आ० 4872.—केन्द्रीय सरकार धातुत्पादक खान विनियम 1961 के नियम 36 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में, इक्कतीस दिसम्बर 1975 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति (जब तक कि उसके पास यान्त्रिक इंजीनियरी में उपाधि या डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्रयोजनार्थ अनुमोदित समतुल्य अर्हता न हो) खानों के प्रमुख निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से और शर्तों के अध्यधीन रहने पर ही जैसा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उक्त विनियम के उपविनियम (1) के उक्त द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट विवरण की खान में उक्त विनियम के उपविनियम (1) के अधीन मशीन का साधारण प्रभार धारण करने और उसके संस्थापन रखरखाव और सुरक्षित कार्यकरण उत्तरदायी होने के लिए नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

[सं० एस० 66013/1/74-एम० आई]

टी० एस० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

S.O. 4872.—In pursuance of the second proviso to sub-regulation (1) of regulation 36 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, the Central Government hereby notifies the 31st day of December, 1975 as the date fater which no person (unless he holds a degree or diploma in mechanical engineering or equivalent qualification approved for the purpose by the Central Government) shall, except with the previous permission in writing of the Chief Inspector of Mines and subject to such conditions as he may specify therein, be appointed to hold general charge of machinery and to be responsible for its installation, maintenance and safe working under sub-regulation (1) of the said regulation in a mine of the description specified in the said second proviso to sub-regulation (1) of the said regulation.

[No. S. 66013/1/74-M.I]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1975

का० आ० 4873.—केन्द्रीय सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3595 तारीख 28 अक्तूबर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए तांबे की खानों में नियोजित कर्मकारों के उन प्रवर्गों को जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जैसी कि वे इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, नियत करने के लिए की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर, उस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उनपर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	प्रतिदिन मजदूरी की न्यूनतम दर
1	2
	रुपये
अकुशल :	
आया, बेकर (हस्त का प्रयोग करने वाला) बेलदार (कैन्टीन), चौकीदार, क्लीनर, रसोइया, सहायक, हथौड़ेवाला, ट्रैमर, मजदूर (पुरुष या स्त्री), ऑफिस बॉय, चपरासी/संदेशवाहक, सर्वेक्षण खलासी, झाड़ूकश (पुरुष या स्त्री), चौकीदार, पानीवाला, अन्य प्रवर्ग जो अकुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	5.80
अर्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षक पर्यवेक्षीष्ट :	
विस्फोटक (ब्लास्टर) का सहायक, फिटर का सहायक, सहायक ड्रिल प्रचालक, बेकर (यांत्रिक साधित्रों का प्रयोग करने वाला), बटलर-एवं-रसोइया, केयर-टेकर रसोइया, बेकर, औषधालय सहायक, मददगार (काष्ठकार, लोहाकार), राज, यांत्रिक (खनन) बत्तीकक्ष परिचर, पम्प परिचालक, माली, खनन मेट काँटेवाला, सेम्पलर, टेलीफोन प्रचालक, अप्रशिक्षित शिशुग्रह परिचालक, संवातन पंखा, परिचालक, अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल, या अकुशल पर्यवेक्षी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	7.25
कुशल :	
एयर विंच, कुलाई परिचारक, ऑटो-बिजली मिस्त्री, कंक्रीट मिश्रण प्रचालक, चार्जमैन काष्ठकार, कम्पा-उण्डर, रसायनज्ञ, ड्रिलयांत्रिक, ऑटो चालक, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, फैरो चालक, होमस्ट प्रचालक, लाइनमैन, यांत्रिक, राज, दाई, मिस्त्री, पम्प-प्रचालक, कुशल मजदूर, पर्यवेक्षक (यांत्रिक), प्रस्तर दलित्र प्रचालक, ट्रक चालक, लोको चालक, लिम्को लोडर प्रचालक, सर्वेक्षक, खरादी, टिम्बर मिस्त्री, तारमिस्त्री, झलाईगर, वाईडिंग इंजनचालक, भारसाधक, पहरा और निगरानी, अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हैं।	8.70
लिपिकीय :	
लेखाकार सहायक, लिपिक, पत्रिका लिपिक, रोकड़िया, मुंशी, अभिलेखापाल, फाइल लिपिक, भण्डारी, टाइमकीपर, आशुलिपिक टंकक अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	8.70

इस सूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :

(1) (क) अकुशल कार्य :— वह कार्य है जिसमें बहुत थोड़ी या या कुछ भी कुशलता या कार्य का अनुभव की अपेक्षा न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हों,

(ख) अर्द्ध कुशलकार्य :— वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) कुशल कार्य :—वह कार्य है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षण के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

(2) प्रस्थापित मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर जीवन खर्च भत्ता आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो का नकदी मूल्य , सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(3) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(4) जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी समझी जाएंगी।

(5) अठारह वर्ष से कम आयु के और निशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को देय दरों की 70 प्रतिशत होगी।

[सं० एस- 32019(12)/75-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू०)]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

New Delhi the 28th October, 1975

S.O. 4873.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of subsection (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Notification No. S.O. 3595 dated 28th October, 1972, for fixing the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule, annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Copper mines as specified in the corresponding entires in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration on or after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rate of wages per day
1	2
UNSKILLED	
	Rs.
Ayah, Breaker (using Manual appliances), Beldar (Canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, Hammer-man, Trammer, Mazdoor (Male or female) Office-boy, Peon/Messenger, Survey Khalasi, Sweeper (Male or Female), Watchmen, Watermen, other categories by whatever name called which are unskilled.	5.80
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant to Blaster, Assistant to Fitter, Assistant Drill Operator, Breaker (using Mechanical appliances), Butler-cum-Cook, Caretaker, Cook, Checker, Dispensary attendant, Helper (Carpenter, Blacksmith) Mason, Mechanic, Mining), Lamp-room-Attendant, Pump Attendant, Mali, Mining Mates, Points-man, Sampler, Telephone attendant, Untrained Crech attendant, Ventilation-Fan-attendant. Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	..
SKILLED	
Airwinch, Haulage Operator, Auto-Electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor-Operator, Concrete Mixture Operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, Chemist, Drill Operator, Drill Mechanic Driver Auto, Electrician, Foreman, Fitter, Ferro Driver, Hoist operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump Operator, Skilled Mazdoor, Supervisor (Mechanic) Stone Crusher Operator, IMCO Driver, Loco Driver, Limco Loader Operatory, Surveyor, Turner, Timber Mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Winding Engine Driver, Incharge Watch & Ward, Other Categories by whatever name called which are skilled.	8.70
CLERICAL	Rs.
Accountant, Assistant, Clerks, Magazine Clerk, Cashier, Muneshi, Record Keeper/File Clerks, Store Keeper, Time Keeper, Stenographer, Typist, Other categories by whatever name called which are clerical.	8.70

Explanation : For the purpose of this notification:—

1. (a) Unskilled work : is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-Skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which call for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed are all, inclusive rates including the basic rate, the cost or living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates notified under this notification, the higher rates shall be treated and minimum rates of wages for the purpose of this notification.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 70% of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019(12)/75-WC(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975